employees want to go back to the Old Pension Scheme, which is somewhat beneficial to them. I think, this is a very important subject.

Sir, I would conclude by saying one more thing. Time and again, I have raised this matter on the floor of this House that in the public sector General Insurance Industry, which is the profit-making insurance industry, employees are deprived of their wage revision for the last ten years. Please do something in this regard and come to their rescue. You are dismantling the public sector.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Please conclude.

SHRI ANIL DESAI: This step will be detrimental to the health of the economy of the country. Please look into it. Thank you very much, Sir, for giving me time to participate in this important discussion.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you. Message from Lok Sabha; Secretary-General.

MESSAGE FROM LOK SABHA

The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2022

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha :-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2022, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 30th March, 2022."

Sir, I lay a copy on the Bill on the Table.

DISCUSSION ON THE WORKING OF THE MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT - *Contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Next speaker is Shri Ram Chander Jangra.

श्री रामचंद्र जांगड़ा (हरियाणा) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लेने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। अभी सीनियर माननीय सदस्यों ने काफी विस्तार से बातें कही हैं। अपने देश के अंदर लंबे समय तक मैकाले की शिक्षा पद्धति रही, जिसमें क्लर्क पैदा किए गए, कामगार पैदा नहीं किए गए। यह शिक्षा पद्धति किनके शासन काल में चलती रही, यह सारा देश जानता है। माननीय दिग्विजय सिंह जी बार-बार बीएमएस की चर्चा कर रहे थे और इलामारम करीम जी भी बार-बार बीएमएस की चर्चा कर रहे थे। अभी मनोज जी ने कहा कि इसमें CITU और उनकी भी चर्चा होनी चाहिए थी। दिग्विजय सिंह जी ने आरोप लगाया कि जनसंघ तो शुरू से ही सार्वजनिक क्षेत्र के कामों के लिए विरोध में रहा है। मैं सदन की जानकारी के लिए कहना चाहता हूँ कि बीएमएस के संस्थापक, सफेद कपड़ों में संत, दत्तोपंत ठेंगड़ी जी जनसंघ के द्वारा इस सदन में आए और लंबे समय तक इस सदन के सदस्य रहे। उनका सदन में चर्चा का जो volume है, वह सबके सामने है। आप लोग उसे कभी भी देख सकते हैं। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उनके विज़न को माना है, उनके विज़न पर काम किया है। उन्होंने मजदूरों, श्रमिकों की भलाई के लिए जो कहा, इस संबंध में उनका विज़न उनकी volume में विराजमान है। हमने उनका अनुकरण किया है और मजदूरों की भलाई के लिए जो काम किए हैं, मैं उन सभी की चर्चा तो नहीं कर सकता हूँ। हमारी पार्टी तो उस सिद्धांत को भी मानती है कि "निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय", बुजुर्ग को घर में रखना भी बड़ा अच्छा होता है, बुजुर्ग का थप्पड़ भी बड़ा कल्याणकारी होता है, उससे भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं और इन्हें किसी बुजुर्ग ने सलाह भी दी, तो उसने इमरजेंसी में 19 महीने की जेल काटी है। हम उस सिद्धांत के नहीं हैं।

महोदय, मैं यहाँ पर एक-दो संस्थानों की चर्चा करना चाहता हूँ। हमारे हरियाणा प्रदेश में रोहतक के अंदर एक Mohan Spinning Mill थी। उसमें तीन शिफ्टों के अंदर दस हज़ार कर्मचारी काम करते थे। वहाँ हथौड़े और दराती के निशान के साथ यूनियन का लाल झंडा टंगा, हड़ताल हुई और वह फैक्ट्री बंद हो गई। उस mill के अंदर सबसे उन्नत किस्म का धागा बनता था। आपमें से कई लोग ऋषिकेश गए होंगे। वहाँ पर एक आईडीपीएल नामक कंपनी थी, Indian Drugs and Pharmaceuticals Ltd., उसमें विश्वस्तरीय दवाइयों का निर्माण होता था। वह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी थी। उसके अंदर यूनियन का लाल झंडा टंगा, नारेबाजी शुरू हुई और आज वहाँ पर जाकर देखिए, उस कंपनी की हजारों एकड़ जमीन पर घास उगी हुई है। वह कंपनी सबसे ज्यादा गुणवत्तापूर्वक दवाइयाँ बनाती थी। इन लोगों ने इस देश का क्या हाल किया है, यह सबको पता है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। अभी यहाँ पर सुश्री दोला सेन जी नहीं बैठी हैं। उन्होंने महिलाओं के विषय में बात की, बेरोजगार युवकों के बारे में बात की कि बीए, एमए, पीएचडी करने के बाद भी युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि देश में लंबे समय तक स्किल इंडिया का कोई प्रोग्राम क्यों नहीं चलाया गया? हमारे देश में मैकाले की शिक्षा पद्धति रही है, उसका रोजगारी रेट बीए, एमए करने के बाद भी चार प्रतिशत रहा है, जबकि अमेरिका में यह 40 प्रतिशत है और साउथ कोरिया में 96 प्रतिशत है। वहाँ ग्रेजुएट होने के बाद 96 प्रतिशत लोग बेरोजगार नहीं रहते, वे रोजगार ढूँढ़ लेते हैं, उनके हाथ में कोई न कोई हुनर होता है, लेकिन यहाँ पर केवल और केवल क्लर्क पैदा किए गए। पहले 'मेक इन इंडिया' का नारा क्यों नहीं लगाया गया? अगर चाकू की जरूरत पड़े, इंग्लैंड से मंगा लो, पिस्टल की जरूरत पड़े, स्पेन से

मंगा लो, कंप्यूटर की जरूरत पड़े, जापान से मंगा लो, घड़ी की जरूरत पड़े, स्विट्ज़रलैंड से मंगा लो, मोबाइल की जरूरत पड़े, चीन से मंगा लो, लेकिन 'मेक इन इंडिया' का नारा क्यों नहीं लगाया गया? 'मेक इन इंडिया' का नारा क्यों नहीं दिया? यह केवल नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार को ही क्यों याद आया, यह सोचने का विषय है। **...(व्यवधान)...** यह जिस बीएमएस की चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं के विज़न के अनुसार यह काम हो रहा है। यह Dattopant Thengadi ji का ही vision है, जिन्होंने बीएमएस की स्थापना की। वे सबसे बड़े मजदूर नेता रहे हैं, संघ के चिंतक रहे हैं, सफेद कपड़ों में संत रहे हैं, लंबे समय तक इस माननीय सदन के सदस्य रहे हैं और जनसंघ की वजह से रहे हैं। महोदय, यहाँ पर बार-बार बीएमएस की चर्चा की गई, सीटू की कोई चर्चा नहीं की, इंटक की कोई चर्चा नहीं की - यह मनोज जी कह रहे थे। अपने गिरेबां में झांककर देखिए कि आप लोगों ने क्या किया है! मैं अभी पिछले दिनों बेंगलुरु गया था। वहाँ मैं Indian Aeronautics Limited Company के अंदर गया था। वहाँ मुझे मैनेजर ने बताया कि जांगड़ा जी, अगर हम वर्ष 2014 से पहले रक्षा के संबंध में एक छोटा सा equipment भी चाहते थे, तो उसे विदेशों से मंगवाते थे, लेकिन आज 2014 के बाद हम अपने देश से 70 देशों को रक्षा उपकरण निर्यात कर रहे हैं। आखिरकार, 'मेक इंन इंडिया' के माध्यम से ही बेरोजगारी मिटेगी। **...(व्यवधान)...** सर, मेरी आयु 72 साल की है। हमें याद है कि हिन्दुस्तान का प्रत्येक गाँव एक स्वतंत्र इकाई था। गाँव के अंदर जुलाहा भी था, गाँव के अंदर कुम्हार भी था, गाँव के अंदर * भी था, गाँव के अंदर कारपेंटर भी था, गाँव के अंदर लुहार भी था। हर गाँव एक संपन्न इकाई था, आत्मनिर्भर इकाई था। अगर सारे लुहारों का काम एक बड़ी कंपनी को दे दिया गया, तो वह किसने दिया? अगर सारे बुनकरों का काम बड़ी कंपनियों को दे दिया गया, तो वह किसने दिया, यह सोचने का विषय है। **...(व्यवधान)...**

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Sir, point of order.

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): ऑनरेबल मेम्बर, एक मिनट।

PROF. MANOJ KUMAR JHA : No animosity. ...*(Interruptions)*... No animosity. ...*(Interruptions)*... While narrating the names of the castes, he has used the name of a caste which has been considered unparliamentary. It is just that. No animosity.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): We will examine it. माननीय सदस्य, आप अपनी बात continue करें। **...(व्यवधान)...**

श्री रामचंद्र जांगड़ा : सर, चमड़े का काम करने वाला अपने आप में ही यह मानता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लोहे का काम करने वाला हर आदमी यह मानता है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें defamation की कोई बात नहीं है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

सर, मैं यह कह रहा था कि देश में लम्बे समय तक यह व्यवस्था क्यों चलती रही? यह बेरोज़गारों की फौज किसने खड़ी की है, यह एक सोचने का विषय है। किन लोगों ने ऐसे कानून नहीं बनाए, जिसके कारण बेरोज़गारों की फौज खड़ी हुई?

आज माननीय प्रधान मंत्री जी के विज़न से नई शिक्षा नीति आई। उस नई शिक्षा नीति के नये नियमों को मैं आपको शॉर्ट में पढ़कर सुनाता हूँ। 2025 तक कम से कम 50 प्रतिशत स्कूली शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमें अंग्रेज़ियत का पाठ पढ़ा दिया गया कि अंग्रेज़ी बोलने वाला, अंग्रेज़ी जानने वाला शायद बहुत बड़ा आदमी होगा। लोहिया जी कहते थे, *"बड़े आदमी की क्या पहचान, बोले गिटपिट करे न काम।"* अंग्रेज़ियत का एक phobia लगा दिया गया, हमारे विद्यार्थियों का दिमाग ठस कर दिया गया और आज उनको दो का पहाड़ा भी याद नहीं है।

महोदय, मैं अभी कोलकाता गया था, वहाँ हमारी कमिटी का टूर था। वहाँ एक आदमी ने बड़ी रोचक बात बताई। प्रफुल्ल चन्द्र घोष, जो पश्चिमी बंगाल के पहले मुख्य मंत्री बने, उन्होंने लोगों से पूछा कि अंग्रेज़ लोग, जो फैक्टरियाँ चलाते थे, वे उनको छोड़कर चले गए, तो वे फैक्टरियाँ अभी बन्द हैं या चल रही हैं? उन्होंने अपने सेक्रेटरी को उन फैक्टरियों को देखने के लिए भेजा। सेक्रेटरी ने उनको बताया कि सारी फैक्टरियाँ चल रही हैं। उन्होंने पूछा कि उनको कौन चला रहा है? इस पर सेक्रेटरी ने बताया कि उनको पंजाब और राजस्थान के मारवाड़ी लोग चला रहे हैं। जब उन्होंने पूछा कि जो लोग फैक्टरियाँ चला रहे हैं, उनकी कितनी एजुकेशन है, तो बताया गया कि उनमें से मुश्किल से कोई पांचवीं या आठवीं पास है। उनमें से कोई भी दसवीं पास नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारी प्राथमिक शिक्षा में भी हमें 19 का पहाड़ा, ढाई का पहाड़ा, ऊंटे का पहाड़ा, सवैया का पहाड़ा, पौने का पहाड़ा, यह सब कुछ याद था। अंग्रेज़ियत ने यह किया कि अगर बच्चे से अब हम पूछें कि दो जमा दो कितने होते हैं, तो इसके लिए भी वह कैलकुलेटर उठाएगा, क्योंकि उसको कुछ याद नहीं है। हमारी शिक्षा नीति की यह देन रही कि हमने अपने आपको ठस कर लिया। मतलब, हमारा दिमाग बिल्कुल कैलकुलेटर और कम्प्यूटर के ऊपर आधारित हो गया, जबकि वे पांचवीं और आठवीं पास लोग भी फैक्टरियाँ चलाते थे। आज भारत की शिक्षा नीति में यह प्रावधान किया गया है कि प्राथमिक शिक्षा अपनी मातृभाषा में दी जाएगी, यह देश के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। यह एक संकल्प लिया गया है। मैं शिक्षा नीति की चर्चा कर रहा था कि उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा उद्योग तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी में व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह बहुत लम्बा विषय है, लेकिन मैं इस बारे में कुछ आँकड़े देना चाहता हूँ। मैं सारे आँकड़े यहाँ नहीं दे सकता, क्योंकि समय कम है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आपके बाद आपकी पार्टी से पाँच और स्पीकर्स हैं, इसलिए आप उसी हिसाब से बोलिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा : सर, मैं और कितने समय तक बोल सकता हूँ?

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : अगर आप दो-तीन मिनट में कन्क्लूड करें, तो अच्छा रहेगा। **...(व्यवधान)...**

श्री रामचंद्र जांगड़ा : महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि मैं थोड़ी आँकड़ों की भी बात कर लूँ। अभी श्रमिक संस्थाओं की भी चर्चा हुई, महिलाओं के ऊपर भी चर्चा हुई और श्रम ब्यूरो की भी चर्चा हुई। पहले हमारे श्रमिकों के लिए हॉस्पिटल्स की क्या व्यवस्था थी? ESIC का निर्माण माननीय मोदी सरकार के समय में हुआ। मैं आपको थोड़े से आँकड़े बता दूँ। मानेसर गुरुग्राम के बिल्कुल नजदीक है, वहाँ पर ESIC में 500 बिस्तरों वाले अस्पताल की आधारशिला रख दी गई है। उसके लिए जमीन ले ली गई है और काम शुरू कर दिया गया है। उसके बाद हमारे असम के तिनसुकिया में जो हॉस्पिटल्स थे, उनको निगम के अधीन ले लिया गया है, उनमें सारी सुविधाएं प्रदान करनी शुरू कर दी गई है। मैं छोटे-मोटे आंकड़े बता रहा हूं, वैसे यह विषय बहुत लम्बा है। अभी महिलाओं की चर्चा हो रही थी। मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं कि नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार आने के बाद हमारी महिलाओं के लिए दो जीवित बच्चों तक सवैतनिक मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया है, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों के संबंध में शिशु सदन का अनिवार्य प्रावधान शामिल किया गया है। पहली बार दत्तक ग्रहण माताओं के लिए भी 12 सप्ताह का सवैतनिक मातृत्व अवकाश शुरू किया गया है। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार ने किया है, पहले किसी सरकार ने हमारी महिलाओं के बारे में यह बात नहीं सोची थी।

महोदय, इसके अलावा मैं आपको कुछ और आंकड़े देना चाहता हूं। श्रमिकों के लिए जो बोनस की बात है - अभी यहां चार नियमों की चर्चा हो रही थी कि इतने नियमों को मिलाकर चार नियम बना दिए गए। बोनस के लिए सर्वाधिक पात्रता सीमा को दिनांक 01.01.2016 को 10 हज़ार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20 हज़ार रुपये प्रतिमाह करने के लिए अधिसूचित किया गया है। सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मज़दूरी की सीमा को साढ़े तीन हज़ार रुपये से बढ़ाकर सात हज़ार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है, यह 1 अप्रैल, 2014 से प्रभावी है। मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूं, आज मैं गाँव की स्थिति के ऊपर चर्चा कर रहा था - मैं दत्तोपन्त ठेंगड़ी जी का बीएमएस का विज़न बता रहा हूं - मैं गाँव के ऊपर चर्चा कर रहा था कि गाँव के अंदर यह बेरोज़गारी क्यों पैदा हुई। प्रत्येक गाँव एक स्वतंत्र इकाई था। जैसी मैंने चर्चा की कि वहां सभी जातियां अपना-अपना काम करती थीं, वे आत्मनिर्भर थीं। मैं पूछता हूं कि इस लम्बी व्यवस्था के अंदर कोई कुम्हार भाई किसी भट्टे का मालिक क्यों नहीं बना? कुम्हार ने इस संसार को मिट्टी की कला, ईंट पकाने की कला और घड़ा पकाने की कला दी है। किसान की फसल की एमएसपी की बहुत चर्चा होती है, मैं कहता हूं कि कुम्हार के एक मटके की एमएसपी तय कीजिए, उसको मिट्टी खोदने, कूटने, उसको सानने, उसको चाक के अंदर लगाने, फिर आग के अंदर पकाने और पीटने तक दो हज़ार रुपये से कम में कोई मटका नहीं पड़ सकता, लेकिन कुम्हार का मटका दो सौ रुपये के अंदर बिकता है, यह सोचने का विषय है। आज देश के अंदर जो ईंट पकाने के भट्टे हैं, कोई कुम्हार उनका मालिक नहीं है, कुम्हार तो गधा लेकर उसमें मज़दूरी कर रहा है, वह तो बेचारा उसका मज़दूर है। कोई गाँव का चमड़े का कारीगर किसी चमड़ा फैक्ट्री का मालिक नहीं है, वह उसके अंदर मज़दूरी कर रहा है। गाँव का कोई बढ़ई किसी फैक्ट्री का मालिक नहीं है, वह फैक्ट्री के अंदर मज़दूरी का काम कर रहा है। गाँव का कोई लोहार किसी फैक्ट्री का मालिक नहीं है, वह उस फैक्ट्री में मज़दूरी कर रहा है। दिग्विजय सिंह जी, यह व्यवस्था किसने खड़ी की? आज बहुत से शिल्पकार गाँव में हुनर लिए हुए हैं। नरेन्द्र मोदी जी ने उनके हुनर को पहचाना है।

गाँव के अंदर एक बढ़ई अच्छी बैलगाड़ी बनाना जानता है, लेकिन मार्केट में बैलगाड़ी की डिमांड नहीं है, वह क्या करेगा? अब ट्रैक्टर्स आ गए हैं। लोहार के इक्विपमेंट्स की बात की जाए, आज हमारे जो गाड़िया लोहार हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आप conclude कीजिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा : उपसभाध्यक्ष महोदय, आज गाँव के अंदर गाड़िया लोहार हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आपको जितना समय दिया गया था, वह पूरा हो चुका है।

श्री रामचंद्र जांगड़ा : वे बेचारे छोटी-मोटी चीज़ें बेचकर अपना गुज़ारा करते हैं, लेकिन आज उनकी बनायी हुई चीज़ की कोई डिमांड नहीं है, इसीलिए वे बेरोज़गार हैं। उनके हाथ को आधुनिक हुनर दिया जाए और आधुनिक टेक्नोलॉजी दी जाए और उनको प्रशिक्षण देकर रोज़गार के अवसर दिए जाएं। यह विज़न अगर देश में किसी ने पैदा किया है तो हमारे प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने किया है, अन्य किसी ने नहीं किया है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आप conclude कीजिए।

श्री रामचंद्र जांगड़ा : महोदय, मैं अपनी बात को conclude करता हूं। इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का और हमारी सरकार का धन्यवाद करता हूं कि वह श्रमिकों की भलाई के लिए, मज़दूरों की भलाई के लिए बहुत बेहतरीन एक्ट लेकर आई है, बेहतरीन प्रोविज़न लेकर आई है, प्रावधान लेकर आई है। Labour Employment की जितनी भी सिफारिशें हैं, जितने भी प्रावधान किए गए हैं, मैं उन सभी के लिए प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : श्री पि. भट्टाचार्य। माननीय भट्टाचार्य जी, आपके बाद आपकी पार्टी से एक और स्पीकर हैं।

श्री पि. भट्टाचार्य (पश्चिमी बंगाल)**:** सर, आपने मेरे previous speaker को बहुत टाइम दिया है।

डा. सस्मित पात्रा : उनके पास उतना समय है।

श्री पि. भट्टाचार्य: वह अलग बात है। उसी हिसाब से आपको थोड़ा टाइम हमें भी देना पड़ेगा। I am very sorry. Anyway, today is really a very important day. We are discussing the labour and employment issue. It is one of the oldest Ministries in the Central Government and also in the State Governments but, unfortunately, I feel that this Government is trying to destroy the strength and power of the workers. They say that they have introduced so many social programmes but what type of social

programmes? Digital India! They have told about Shram Suvidha Portal. I would like to tell the hon. Minister. You are a lawyer. You know something about the law. You tell me, what would an agricultural labour do with this portal and the digital thing when he has no work? All over the country, there are crores of agricultural workers who are working in the fields. How much money are they getting every day? You told that you have common registration format on the e-biz portal of Department of Industrial Policy and Promotion. What industrial policy and promotion in regard to the agricultural labour and all the workers who are covered by the Minimum Wages Act? Can you tell me about crores of workers, who are covered under the Minimum Wages Act, such as *beedi mazdoor,* rickshaw puller and so many such workers who are there? How are you going to protect them? How are you going to give them their minimum wages? There is no scope at all. The Government has said: "Yes, simplification and reduction of number of registers to be maintained under various Central labour laws." What are the labour laws? You have squeezed all the labour laws. For whom? In a practical sense, we had 40-42 labour laws. Now, four courts are there for protection. How can you give protection to the agricultural labour, both the unorganized sector workers and the organized sector workers? You tell me. You are a lawyer, you tell me. In a labour court, the judges say: "We have no law at all to protect the workmen." Five years, six years, ten years in waiting, they do not get any verdict. After getting any verdict in their favour, do you know what happens? Your management is going to the High Court and Supreme Court. But, you tell me how a poor worker can go to the Supreme Court. Why will the Minister of the Government of India not protect these workers? Then, what for is this Labour Ministry? You kindly tell me what for this Labour Ministry is. Then, we should change the name of the Labour Ministry. We may say that it is a Ministry for management, industrialists and the corporate sectors. Really, I am very sorry to tell all these things to you. 'सबका साथ, सबका विकास' - विकास किस का होता है? Management का विकास होता है। Taxation reduction - यह वर्कर्स के लिए नहीं होता है। यह management के लिए होता है। But, you are the Labour Minister. You have to protect the workmen. Regarding provident fund, do you know and have you had any statistics as to how many workers are not getting the provident fund? Your officers can do this thing and can tell you. Can your officials tell us or can the Minister tell in this House as to how many industrialists were punished because they are the defaulters of provident fund? Can you tell me this? I can say it to you that it is more than two hundred. Jute mill owners who are the defaulters, no case has yet been lodged against them. Why? Now, we are saying that urbanization will take place. I agree and I support it. Industrialization will take place. I support it. But, when you will remove the villagers

where will they be going? How can you provide help to them? Is there any provision that you have? No; you don't have anything. We know that in our country, not only our country but all over the world...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, your other speaker will only have five minutes with him. You take a minute or two because that is the total time allocated for your party. You take a minute or two.

SHRI P. BHATTACHARYA: So, all over the world, in a production unit, you require the management, I understand but can any production take place without the labour force? Labour force is the most important factor in a production unit but if you don't protect them, how can you get the production? विकास करने के लिए तो प्रोडक्शन जरूरी होता है। यह कैसे होगा, if you are trying to kill the workers. The name of the Ministry is Labour & Employment. Where is the employment? I understand that due to the Covid and demonetization, lakhs of workers have become unemployed and mostly are the child workers. Here is a figure. According to a study by SBI Research, the share of the informal sector in Indian economy fell to 15 to 20 per cent in Financial Year 2021 from 52.4 per cent in Financial Year 2018. There is poverty in rural India. Evidence of declining consumption spending in rural India bears this out. According to a Government survey, in 2018 rural households were spending 8.8 per cent less, after accounting for inflation, than they were six years ago, even as urban spending grew by 2 per cent. This was the first such decline in, at least, five decades.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, please conclude.

SHRI P. BHATTACHARYA: Rural households had to reduce their spending on food by massive 10 per cent, worsening India's hunger crisis...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Bhattacharya*ji*, please conclude. I cannot allow you more time. I have already given you nine minutes. There are only three minutes left for your other Member. Please conclude.

SHRI P. BHATTACHARYA: I have only one minute.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have less than a minute. You have already taken three more minutes. Just one more minute and please conclude.

SHRI P. BHATTACHARYA: Anyway, I am trying to cut short these things. Child labour raised to huge number. In 2016, the Government estimated that there were 100 million migrant workers of which roughly 20 to 25 per cent were children. According to UNICEF, more than ten million Indian children are still in some form of servitude with over 1.5 million schools closed during the pandemic. You know it very well, Sir, that so many schools were closed. That is number one.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Thank you.

SHRI P. BHATTACHARYA: Just two more minutes, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I cannot allow more time. You had a total of 12 minutes.

SHRI P. BHATTACHARYA: Sir, just one minute to conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): That one minute has been continuing. Please conclude.

SHRI P. BHATTACHARYA: The children engaged in meaningful development activities have also gone away or reduced significantly. How can we protect the workers, particularly, the child workers? Lastly, I would like to know from the Government whether they are going to change the Child Labour Prohibition Act and making all arrangements that those who will employ child workers, will be punished and sent to jail. This I would like to know from the Government.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now Shri G.K. Vasan. You will have four minutes among the allotted time.

SHRI G.K. VASAN (Tamil Nadu): Sir, workers, labourers mean hard work. That is the strength of the nation and also the growth of the nation. In fact, workers are the heartbeat of our nation. We all understand, Sir, that the Government of India has implemented many welfare schemes to the working class, especially, the unorganized workers and migrant workers. Nearly, 92 per cent of workers are working in unorganized sector and the Government support these workers by implementing various schemes. I want to suggest to the hon. Minister for the consideration of the Government. Sir, 2020 has brought a number of crises for our

workers, especially, migrant workers, trade unions, frontline workers. They have faced a lot of problems because of the decline of economic growth due to Covid. ...*(Interruptions)*.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Let us not stand and talk, please. ...*(Interruptions)*.... Please don't stand and talk...*(Interruptions)*. Please sit down. माननीय जॉन ब्रिटास जी, आप बैठ जाइए।

SHRI G.K. VASAN: The Central Government brought about changes in labour laws and labour administration. This process of labour law reforms which was started a few years ago has resulted in a number of laws being reformed into four codes. What are the expectations of our workers? Labour laws need to provide sufficient rights to our workers. Workers need protection on job. Workers need assured minimum wages, social security, health and safety standards and the mechanism for ensuring collective bargaining rights. This means, facilitating forming of trade unions, and having recognized trade unions, bargaining in good faith with them. This could also definitely need a labour administration that effectively manages conflicts and ensure the enforcement of their rights. India's current apprenticeship scheme allows 2.5 per cent to 15 per cent of the organized sector's total workforce. To be apprenticeship in firms with 30 or more employees, they need to mandatorily hire apprentices, which has to be noted by the Ministry. Sir, to conclude, I would like to say, the Employees Pension Scheme, 1995 was introduced by the Central Government on 16.11.1995. Seventy lakhs of senior citizens and their family members of our nation are getting pension through this scheme. This is really affecting their livelihood. Unfortunately, 25 per cent of the 70 lakh pensioners are getting only around Rs.1000 as pension, to be underlined, Sir. The rest of the 75 per cent are getting Rs.1000 to Rs. 2800 per month. They are totally disappointed and not able to earn their regular bread. Sir, I request the Government to implement minimum pension of more than Rs.6,000 per month with DA and implement medical facility on par with GPF pensioners. With this, I conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Shri Abdul Wahab; you have four minutes to speak.

SHRI ABDUL WAHAB (Kerala): Sir, our GDP, I feel this concerns women employment. What we say regarding women employment, empowerment and all, still it is a concern for India comparing other nations like Bangladesh or even other

countries. We are very low in that. So, I urge our Minister, Bhupender*ji*, not only just empowerment, you give job to the women. For that, you have to develop the skill of women especially not much educated women. So, not just Jan Shikshan Sansthan (JSS) and all, you should also empower them more. Give them some extra money from Exchequer, to provide more skill. A lot of skill institutions are there. And, I appreciate the Government of India for allocating Rs.18 crores for skill development and hostels in my State. I appreciate and congratulate our Minister of Minority Affairs for giving us such a big amount for skill development. They should increase more and more such activities. And, women empowerment is the only way to increase our GDP. So, take measures for that. Transform the agriculture sector to recognise women work and reduce disparity between the wages of men and women. Still, it is happening. In all spheres, it is happening. Almost, 60 per cent is the wage for women, when it is coming to work culture. It is a culture in Kerala also. So, try to make it at par either by law or by legislation or whatever it is. Then, encourage women entrepreneurship and MSMEs. Develop vocational skill development center for women only. An Urban Employment Guarantee (UEG) Scheme should be introduced to cater to the needs of the unemployed in urban areas. Institute a scheme in line with MNREGA to offer support during the lockdowns, provide health insurance and increase the number of minimum work days. Gig economy firms that exploit migrant workers of historically dispossessed communities have to be addressed. The Government should formulate laws and norms to guard them from exploitation. One of our leaders present here from the CITU, and another leader in my institution is Shri Binoy Viswam; he is not here now. So, from AITUC and CITU. ...*(Interruptions)*...

THE LEADER OF THE OPPOSITION (SHRI MALLIKARJUN KHARGE): They all left you or what!

SHRI ABDUL WAHAB: No, no. With that one, I can manage. No problem of trade unions. Even from BMS, Shri V. Mulraleedharan is sitting there. ...*(Interruptions)*... Cordial relationship is there. So, it will continue. So, this Gig worker and all, they are not getting anything. Hon. Labour Minister, I hope that everybody is mentioning about that. You should come out, whenever you are replying, with a scheme for these people, unorganised sector. ...*(Interruptions)*... But, if there is a scheme for them, --- not GIG workers and all, I am worried about other workers -- ...*(Interruptions)*... I am worried about their other welfare measures. ...*(Interruptions)*... Regularize them and give them something once they are leaving.

Please do consider about the workers of the unorganized sector when they leave. Thank you.

SHRI KANAKAMEDALA RAVINDRA KUMAR (Andhra Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, I thank you for giving me this opportunity. Sir, the Ministry of Labour and Employment has an important role to play in providing employment to lakhs and lakhs job seekers in the country. The role of the Ministry further assumes significance in the backdrop of COVID-19 pandemic. This Ministry has responsibility to provide jobs and protect the interest of labourers, and maintain balance between employer and employee. Sir, as per the Periodic Labour Force Survey conducted in the year 2017-18, the total employment in the country was around 47 crores. About 9 crore workers were found engaged in the organized sector and the remaining 38 crore workers were found engaged in the unorganized sector. This is an ample proof that there were more persons in the unorganized sector. During COVID-19 pandemic, the unorganized sector workers suffered how much is known to everyone. The unemployment rate in the country is very high. The COVID-19 pandemic induced lockdown has further worsened the situation of the unemployed workers. In this backdrop, the natural question arises in everybody's mind is that how the Government is going to tackle the issue of unemployment? In this regard, I expect a detailed answer from the Minister. Sir, in the speech made by the hon. Finance Minister, Shrimati Nirmala Sitharamanji, during presentation of Budget 2022-23, the Government has announced linking of NCS portal with ASEEM portal of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, portal of the Ministry of Labour and Employment and the portal of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises. This will further enhance the skill based database of candidates on NCS Portal. I, on behalf of my Party, Telugu Desam, wholeheartedly welcome the proposal. Sir, the child labour problem has always remained as a problem in our country. With the aim to eradicate child labour in the country, the Government has launched the national Child Labour Project. It aims to concentrate on 12 child labour endemic districts of the country. In this connection, I would like to know from the hon. Minister whether the number of child labour in endemic districts has reduced or it is going on in the same level. Sir, now I come to ESI, Employees' State Insurance Corporation-run hospitals across the country. They are running medical colleges in certain pocket in the country. I urge the Minister to take necessary steps so that intake of medical in the ESI-run hospitals is considerably enhanced. Sir, after the bifurcation of the united Andhra, the only ESIC medical college that was in Hyderabad went to Telangana. As such there is no ESI-run medical college in the State of Andhra Pradesh. I request

the hon. Minister to open an ESI-run medical college in the State of Andhra Pradesh. Sir, in Andhra Pradesh, no employment generation has taken place after June 2019. The present Government came to power with a promise that after assuming the power they will get huge employment and issue DSA notifications. But the promise has not been implemented like other promises. All the promises made by the present Government are futile as far as election promises are concerned. There is huge unrest and unemployment among the youth of Andhra Pradesh. Sir, another important aspect is that during the last two days the trade unions across the country had called for 2-day strike against the Government's policy which severely affected the various sectors of the Indian economy like banking, farming, fuel costs, etc. It has also been demanded to revoke the proposed changes in labour laws, restrain from privatization of PSUs, extend MNREGA to urban areas, reduce Central Excise Duty on petroleum products, take stringent measures to control price rise and opposing reduction in the tax rate on provident fund accumulation from 8.5 per cent to 8.1 per cent. They also demanded increase in public investment in agriculture, education, health and other major public services. Due to this strike, the day-to-day life of the common people was severely affected. Public sector banks also actively participated in the strike. Due to this, the transactions in the banks were affected. Considering the entire gamut of issues involved in the strike, I urge the Government to be considerate enough to accept the demands of the trade unions in the interest of the nation. Thank you.

6.00 P.M.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN (Maharashtra): Sir, I will come directly to the points and I draw the attention of the Minister to three specific issues. One is that of the bonded labour. Is it not an utter shame that bonded labour is still prevalent?

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Vandanaji, it is six o'clock. Yes, Mr. Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS; AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI V. MURALEEDHARAN): Sir, since the House is discussing the working of the Ministry of Labour and Employment, and a few Members are yet to speak, I suggest that we may extend the sitting of the House today till all the Members speak and the Minister may reply whenever the Legislative Business is taken up.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Is it fine with all the Members?

SOME HON. MEMBERS: Yes, yes.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Okay then. In the end, we will take up Special Mentions.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: The first point is that of the bonded labour. I feel, it is a matter of utter shame that bonded labour still exists in our midst and in the 21st Century.

I still can't get over a picture, a little more than a year back, which went viral of a starved, frail old man, falling at the feet of Tamil Nadu officials, possibly thanking them for rescuing him and his family from bonded labour. One of the lucky persons, rescued from forced servitude! The Government, unfortunately, has no figures in this respect and it has not made an effort to find out how many such people are still living in bonded labour in our country. The 2018 Global Slavery Index estimates that there are eight million people living in slavery in our country in 2016. This amounts to 6.1 victims for every thousand people. We have made laws. Articles 21 and 23 prohibit bonded labour. The Amendment to the Indian Penal Code 370 and 370A are existing. We also made a specific law, the Bonded Labour System (Abolition) Act in 1976. The spectre of bonded labour still plagues our country and not to forget that this includes not only men but also old men, women and children. Sir, the question I want to ask is: Are we doing enough? On the answer, I will leave it to the wisdom of this House and read an observation from an article which is clear enough to say what the Government is doing. It is thus: "A glance at the total Budget and expenditure for rehabilitation of bonded labour points towards the Government's lack of seriousness towards this issue. While the overall funds released for bonded labour rehabilitation were Rs.664.45 lakhs in 2017-18, they dramatically decreased by 61 per cent the following year to Rs.253.3 lakhs. Surprisingly, the Ministry of Labour and Employment spent not a single rupee on their rehabilitation in 2019-20.' Sir, what are we doing? Where are we going to? Bonded labour is something which really is like a cancer in our society. If the Government is not serious about it, it is something that we all need to be very, very concerned about.

Sir, there is a lot to say but I am keeping myself very short. The second point that I would like to touch upon is the manual scavengers. What could be more sensitive than that on the one side, one reads every other day of people dying while cleaning sewers due to the gas suffocation, while on the other, when the Government is asked the question as to how many manual scavengers died in the last five years,

recently, the reply given is a shocking and shameful, 'None'? Cleaning of sewers and septic tanks has now been included in the 2013 Act. Therefore, if the answer is 'none', then what is the kind of news that we read every day in the newspapers? Even here, Sir, the Government, unfortunately, has no figures. Whatever figures are created, it has been by an initiative of the NITI Aayog, which got four Ministries together. They tried to find out the data. But this data was based only on 216 districts out of the 600 districts of our country; that too it didn't cover urban areas and, therefore, the figure that has come out can't be relied upon. According to the numbers collated by the National Commission for *Safai Karamcharis*, the statutory body that was set up by an Act of Parliament for welfare of sanitation progress...

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Hon. Member, you will have to conclude.

SHRIMATI VANDANA CHAVAN: Okay, Sir. I have one important point that I have to make apart from this. One person died every five days on an average while cleaning sewage septic tanks. I will leave out this point of manual scavenging, as the time is short. The Budget of 2022-23, which allotted Rs. 70 crores for rehabilitation of those involved in manual scavenging has been 30 per cent less than the last year's budgetary allocation of Rs. 100 crores.

My last point is on women. According to 2019 UN data, India has one of the lowest female labour force participation rates in the world. It is 21 per cent as compared to 53 per cent which is the global median. I wish to say that we need to do a lot. A comprehensive approach needs to be taken, but I want to seed one thought here, in this House, and please allow me that. I wish to sow the seed of an idea of menstrual leave. There will be arguments 'for' and 'against' and from women themselves because women may face discrimination at workplace, but the happy story is that such policies do exist in various countries like Japan since 1947, Indonesia, South Korea, Taiwan, Zambia and China. Therefore, time has come to play a proactive role and try to see if we can give this. I take this opportunity to congratulate, and I will finish after this, and salute 12 companies in India where our girls have been given the relief of menstrual leave without demanding for it. Therefore, I would like to read out these companies and then finish. It is Swiggy, Culture Machine, Mathrubhumi, Magzter, Wet and Dry Personal Care, IndustryARC, Zomato, IVipanan, Gozoop Online Pvt. Ltd., Horses Stable News, Fly my Biz, Byju's. These are all torch-bearers of gender-specific needs. We seem to be forgetting that we are a welfare State. We seem to be forgetting that we owe a duty to the last man.

It is not a favour we will be doing to them. It is their right and, therefore, the Government needs to take concrete action. Thank you, Sir.

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय के कार्यकरण पर हो रही चर्चा में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। आज के पूर्व वक्ताओं में लेबर लीडर्स और जानकार लोगों ने बहुत बहुमूल्य सुझाव देने का काम किया और श्रमिकों के बारे में, उन्हें रोज़गार देने के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने का काम किया।

महोदय, यह 1960 की बात है, जब मैं दसवीं कक्षा का विद्यार्थी था, तो मेरे दादा जी ने कहा कि तुम अपने खेत में काम करने के लिए जाओ। उस समय के जो जमींदार लोग थे, बड़ी जोत वाले लोग थे, वे लोग सवेरे उठकर मजदूरों को खोजते थे और नौ बजे उसे खेत पर बैठाकर स्नान करने और भोजन करने के लिए चले जाते थे और तीन बजे देखने के लिए आते थे। जब वह तीन बजे वापस आए, तो एक मजदूर को वह अपने खेत में जहां बैठाकर गये थे, वह मजदूर वहीं बैठा रहा। मालिक ने मजदूर से कहा कि तुम्हें नौ बजे जहां बैठाया गया था, तुम वहीं बैठे हुए हो। तो मजदूर ने क्या कहा? मजदूर ने कहा - "हाथ चले गोड़ ठामे-ठाम और जेहन पैसा, ओहन काम।" महोदय, यह मैं 1960 की बात बता रहा हूँ। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूँ। ईंट बनाने वाले मजदूरों के बारे में आपका क्या सुझाव है, सैलून में काम करने वाले मजदूरों के बारे में आपका क्या सुझाव है, रिक्शा चलाने वालों के बारे में आपका क्या सुझाव है, कोलकाता में हाथ से जो रिक्शा चला रहे हैं, उन मजदूरों के बारे में आपका क्या सुझाव है, सोना-चाँदी की दुकानों में मजदूरी करने वालों के बारे में आपका क्या सुझाव है, जूता बनाने वालों के बारे में आपका क्या सुझाव है, होटल में काम करने वालों के बारे में, उन मजदूरों के बारे में आपका क्या सुझाव है, सम्पन्न परिवारों के घर में काम करने वाले मजदूरों के बारे में आपका क्या सुझाव है, कार चलाने वाले, गाड़ी ड्राइवरों के बारे में और खलासियों के बारे में आपका क्या सुझाव है?

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस विभाग के मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इन मजदूरों की संख्या कलेक्ट कीजिए और कोई ठोस निर्णय लेकर उसके बारे में सोचिए और जवाब देने का काम कीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड कीजिए।

श्री राम नाथ ठाकुर : कन्क्लूड करूँ? **...(व्यवधान)...** अभी आपने बोलने कहाँ दिया है और कन्क्लूड करूँ? **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आपके 4 मिनट थे।

श्री राम नाथ ठाकुर : सर, अभी तो मैं खड़ा ही हुआ हूँ। **...(व्यवधान)...** अभी तो मैं बोलने के लिए खड़ा ही हुआ हूँ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। मैं आपसे इन मजदूरों के बारे में कहना चाहता हूँ कि :

"है पेट जहाँ खाली नर का, उस घर में दीप जलेगा क्या।
जब घास न कोई देता है, तो बूढ़ा बैल चलेगा क्या।।"

महोदय, ये जितने कल-कारखाने बन्द हुए, उनको समय-सीमा के अन्दर चलाने के लिए आपने क्या सोचा है? जितने कल-कारखाने थे, वे बन्द हो गये। उन मजदूरों के बारे में आपने क्या सोचा है? मेरा सुझाव है कि आप अगर इन मजदूरों के बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम कीजिए। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ।

श्री दीपक प्रकाश (झारखंड) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपका धन्यवाद। श्रमेव जयते, श्रमेव जयते। महोदय, मुझे इस विषय पर बोलने के लिए आपने मुझे जो अवसर दिया है, ...(**व्यवधान**)... आपने मुझे यह जो अवसर दिया है, उसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूँगा। ...(**व्यवधान**)... साथ-साथ मेरी पार्टी ने श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा में मुझे बोलने का यह अवसर दिया है, इसके लिए मैं अपनी पार्टी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, सबसे पहले मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपने 7 वर्ष 9 महीने के शासनकाल में श्रमिकों के लिए अमृतवर्षा करने का काम किया है। उस अमृतवर्षा में जो अमृत निकला, उसको श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने मजदूरों के पास पहुँचाकर उनके कल्याण के लिए काम किया है, इसलिए इस मंत्रालय के मंत्री जी को भी मैं अपनी ओर से हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। मैं कुछ पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूँगा :

"कर्मभूमि पर फल के लिए, श्रम सबको करना पड़ता है।
ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है।।"

भाइयो, आज बहुत अच्छा अवसर लग रहा था कि आज सब कम्युनिस्ट के लोग, हमारे वरिष्ठ नेतागण, कांग्रेस के नेतागण और राजद के हमारे वरिष्ठ सहयोगी BMS की चर्चा कर रहे थे। उनकी प्रशंसा कर रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा है कि जब सेशन समाप्त होगा, तो भारतीय मज़दूर संघ की सदस्यता जरूर बढ़ेगी। भाइयों, हम सब जानते हैं कि भारत की संस्कृति में श्रम का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में वेदों की पूजा होती है। वेदों में धर्म के 12 पिलरों का उल्लेख किया गया है, जिसमें श्रम को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। उसमें "श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्त ऋते श्रिताः" का उल्लेख है अर्थात् श्रम सबसे महत्वपूर्ण है। यदि धर्म को मानना है, तो श्रम को सबसे महत्वपूर्ण अंग मानना है।

महोदय, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत को उपनिवेश बनाकर रखा गया था और मज़दूर को गुलाम बनाया गया था। उस समय मज़दूरों के इल्म को खत्म किया गया था और लोगों की कौशलता को समाप्त करने का काम किया गया था। इस सदन के वरिष्ठ सदस्य माननीय दिग्विजय सिंह जी ने आज भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का काम किया कि वह कॉरपोरेट का प्रतिनिधित्व करती है। मैं उनको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि देश की आजादी के

बाद प्रथम एवं द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन दिया गया था और इन बड़े उद्योगों के कारण cottage industry समाप्त हुई थी, जिससे गांव में लोगों की मज़दूरी समाप्त हुई थी। आप लोग गांधी जी के नाम पर शासन करने वाले लोग हैं, लेकिन गांधी जी ने cottage industry के बारे में क्या कहा था? मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप गांधी जी के 'trusteeship सिद्धांत' को पढ़ें, उनके 'ग्राम स्वराज' को पढ़ें। मैं कहना चाहता हूं कि आपने गांधी जी को केवल सत्ता का रास्ता बनाने का काम किया, जबकि पंचवर्षीय योजनाओं में बड़े उद्योग स्थापित किए। यदि किसी ने लोगों के हाथ से रोजगार छीनने का काम किया था, तो वह उस वक्त की कांग्रेस सरकार ने किया था। महोदय, समस्या आपने दी है और उसका समाधान मोदी जी कर रहे हैं। हम लोग उस वक्त कांग्रेस सरकार की जो परिस्थितियां थीं, उसके बारे में लगातार यह कहते आये हैं कि,

'उगा सूर्य यह कैसा, कहो मुक्ति का,
उज़ाला हुआ मंदिरों के शिखर पर,
मगर देवताओं के पदों तक न पहुंचा।'

महोदय, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उसने देवताओं के पदों तक, गरीब, जरुरतमंद लोगों की सेवा करने का संकल्प लिया। मैं बताना चाहता हूं कि जब हम 'आत्मनिर्भर भारत', 'समर्थ भारत' और 'श्रेष्ठ भारत' कहते हैं, तो यह आत्मा से कहते हैं और जमीन की सच्चाई के साथ हम अपने इन सपनों को पूरा करने का संकल्प लेते हैं। इसीलिए जब नरेन्द्र मोदी जी Make in India, Made in India, work for india कहते हैं, तो यहां के श्रमिकों का सम्मान, उत्साह और स्वाभिमान बढ़ाने का काम करते हैं। उपसभाध्यक्ष जी, केवल Make In India, Made In India ही नहीं, Made for Global की भी कल्पना की थी, जिसे पूरी दुनिया ने आज निर्यात के मामले में भारत के मज़दूरों की सेवा के संकल्प के रूप में देखा है। इसीलिए तो निर्यात पहली बार 400 अरब डालर के पार हो गया है और उसका श्रेय नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व और यहां के श्रमिकों को है। उपसभाध्यक्ष जी, मैं पौने दो वर्ष के कार्यकाल में पहली बार बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। **...(व्यवधान)...** उपसभाध्यक्ष जी, मैं आपसे संरक्षण और सभी माननीय सदस्यों से समर्थन मांगने के लिए खड़ा हूं। **...(व्यवधान)...** महोदय, मैं ease of doing business के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। आपके शासन काल की चर्चा करना चाहता हूँ।**...(व्यवधान)...** 2014 में Ease of Doing Business में हमारा रैंक 142वाँ था, लेकिन नरेन्द्र मोदी जी की सरकार में, वर्तमान में हमारा 63वाँ स्थान है। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका श्रेय आप भी देना चाहेंगे। नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले समय में Ease of Doing Business में हम पहले स्थान पर भी पहुँचेंगे।

भारत एक labour surplus economy वाला देश है और इसलिए यहाँ पर श्रमिकों का एक बहुत बड़ा स्थान है तथा उसका महत्व भी है। आप बिना श्रमिकों के आगे बढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैं उस कालखंड की भी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, वह औद्योगिक क्षेत्र है, वह माइनिंग का क्षेत्र है। रमेश जी बैठे हुए हैं, वे वहाँ के प्रभारी भी रहे हैं, वे वहाँ की स्थितियों के बारे में जानते हैं। हमने देखा है कि 2014 के पहले वहाँ पर मजदूरों की हालत क्या थी और आज क्या हालत है। 2014 के पहले काँग्रेस के शासन काल में वहाँ पर काबुलीवाला आकर

मजदूरों के हाथ से मजदूरी छीनने का काम करता था, लेकिन आज मजदूर मोदी जी के प्रति आस्था रखते हुए मोदी जी की जय-जयकार कर रहे हैं। आज पर्यावरण का सवाल हो, प्रदूषण का सवाल हो, वहाँ के मजदूरों की छोटी-छोटी बुनियादी समस्याएँ हों, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए मोदी जी की सरकार कृतसंकल्प है।...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : प्लीज़, शांत हो जाइए।...(**व्यवधान**)...

श्री दीपक प्रकाश : महोदय, मैं 2020 की तीन नई श्रम संहिताओं का उल्लेख करना चाहता हूँ। काँग्रेस की सरकार ने अंग्रेजों के समय के काले कानूनों को अपने कार्यकाल तक रखने काम किया था और वे कानून मजदूरों के अहित के थे, लेकिन मोदी जी की सरकार आई और उसने उन कानूनों को बदलने का काम किया, जो मजदूर विरोधी थे।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, कृपया आप conclude कीजिए। आपकी पार्टी की तरफ से आपको दस मिनट का समय दिया गया था, इसलिए अब आप conclude कीजिए।

श्री दीपक प्रकाश : महोदय, मैं अन्य योजनाओं के बारे चर्चा करना चाहता हूँ, इस सरकार की सफलताओं के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, एक राजनीतिक दल का सदस्य भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। मैं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बीच में जाकर ई-श्रम पोर्टल के संदर्भ में उनसे बात कर रहा था और उसको डाउनलोड कराने का काम कर रहा था। मैं यह बात हृदय से कह रहा हूँ, आत्मा से कह रहा हूँ। जब मजदूर बैठ कर ई-श्रम पोर्टल को डाउनलोड करा रहे थे, तो वे प्रधान मंत्री जी को दुआ दे रहे थे और कह रहे थे, 'जुग-जुग जियो मोदी जी, जुग-जुग जियो।'

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आपके दस मिनट पूरे हो गए हैं, इसलिए कृपया अब आप conclude करें।

श्री दीपक प्रकाश : महोदय, मैं इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे स्किल इंडिया हो, चाहे स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे दिहाड़ी मजदूर का सवाल हो, दिहाड़ी मजदूर आज सरकार की योजनाओं का लाभ उठा कर प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रति समर्पित भाव से देश की सेवा कर रहा है।

महोदय, मैं अंत में कुछ पंक्तियाँ माननीय मंत्री जी और मंत्रालय को समर्पित कर रहा हूँ :

"तेरे हौसलों के वार से, रुकावट कि दीवार जरूर गिरेगी,
तुम देख लेना सफलता जरूर मिलेगी।
मंजिल घूमती है तो डरना क्या है,
निशाना तेरा अर्जुन के तीर जैसा होना चाहिए।
मुश्किलें तो बहुत हैं राह में लेकिन,
इरादा तेरा इस देश के वीर जैसा होना चाहिए।
आसमान के सितारे भी हमें राह दिखा देंगे,
अगर मंजिल पाने के लिए हम अपनी जान लगा देंगे।"

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा जी, आपके पास दस मिनट हैं।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा (उत्तर प्रदेश) **:** महोदय, मैं अपनी और अपनी पार्टी की तरफ से आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय, श्रम और रोजगार पर अपने विचार सदन के समक्ष रखने का अवसर प्रदान किया है। महोदय, भारत जैसे विशाल देश के लिए श्रम एवं रोजगार, दोनों ही विषय अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में श्रमिकों के उत्थान व युवाओं को रोजगार प्रदान करने की दिशा में सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। महोदय, 'प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना' के माध्यम से देश के युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर, उनकी क्षमताओं को विकसित कर राष्ट्र के निर्माण में उनका योगदान लिया जा रहा है। सरकार असंगठित क्षेत्रों को संगठित क्षेत्रों की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है। बेरोजगार युवाओं का डेटा तैयार कर उन्हें चिन्हित किया जा रहा है तथा 'मनरेगा', 'आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना' जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कोरोना महामारी के समय प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को हम सभी ने देखा, परंतु इस पीड़ा को माननीय प्रधान मंत्री जी ने समझा और प्रवासी मजदूरों को पंजीकृत कर उनको उनके गाँव में, उनके घर पर ही विभिन्न माध्यमों से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। मैं इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। महोदय, 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। असंगठित श्रेत्र के श्रमिकों को श्रम कार्ड, पेंशन तथा बीमा जैसी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। हाल ही में सरकार द्वारा शुरू की गई 'ई-श्रम कार्ड योजना' अपने आप में अद्वितीय है। मैंने यह गाँव में देखा है कि जिस भी श्रमिक को इस योजना का लाभ मिल रहा है, वह वास्तव में मन और हृदय से माननीय प्रधान मंत्री जी को दुआएं दे रहा है। इस योजना से असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे श्रमिकों को आर्थिक लाभ मिलने के साथ-साथ, सरकार को देश में श्रमिकों की वास्तविक संख्या का पता भी चल सकेगा। इस डेटा से सरकार इन श्रमिकों के घर तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाएगी। महोदय, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि श्रम कार्ड के मामले में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम स्थान रहा है।

महोदय, वर्ष 2014 में माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार बनने के पश्चात संगठित एवं असंगठित, दोनों ही क्षेत्रों में सरकार द्वारा बड़े बदलाव लाए गए हैं। इन बदलावों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, क्योंकि पहले की सरकारों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को प्राथमिक तथा पारंपरिक स्त्रोत से सीधा सेवा में बदलने का काम किया गया। इन दोनों क्षेत्रों के बीच में उत्पादन की जो श्रृंखला थी, उसे छोड़ दिया गया। महोदय, देश के श्रमिक अपने अधिकारों से वंचित रहे, इसका सबसे बड़ा कारण यही है। आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में देश में 'मेक इन इंडिया', 'स्टार्टअप इंडिया' और ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से उत्पादन करने वाली इकाइयों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे बरसों-बरस तक उद्योगपतियों के हितों को देखकर योजनाएं बनाने वाली पहले की सरकारों में बैठे लोगों को पीड़ा हो रही है। आज ये लोग श्रमिकों को उनके अधिकार दिलाने की बात करते हैं, परंतु काँग्रेस के शासनकाल में

ऐसी हज़ारों घटनाएं हुई हैं, जिसमें देश के मजदूरों, श्रमिकों पर लाठियाँ चलाई गईं, उन पर गोलियाँ चलाई गईं। सर, मैं अभी एक बहुत ही वरिष्ठ सदस्य, दिग्विजय सिंह साहब की बातें सुन रही थी, मैं उनका बड़ा सम्मान करती हूँ। वे प्रधान मंत्री जी के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग कर रहे थे। मैं उनको उदाहरण के तौर पर बताना चाहती हूँ कि उनकी सरकार में मज़दूरों और श्रमिकों के साथ जो किया गया, वह शायद उनको याद नहीं है। मैं उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि नेहरू जी के नेतृत्व में तेलंगाना में किसानों पर गोलियाँ चलीं और काकद्वीप की गर्भवती नारी अहिल्या को गोलियों से भून दिया गया। इतना ही नहीं, राजनंदगाँव कपड़ा मिल के दो मजदूर नेताओं की बंदूक से हत्या भी नेहरू जी के जमाने में की गई है। इंदिरा जी के शासनकाल में हज़ारों क्रांतिकारियों को नक्सली बताकर उनको गोलियों से उड़ा दिया गया था। तुर्कमान गेट, तेलंगाना, भोजपुर आदि में कई बार इंदिरा गांधी जी की सरकार द्वारा गोलियाँ चलवाई गईं। महोदय, तब ये लोग मौन थे। इनको तब किसानों और श्रमिकों की याद नहीं आ रही थी। आज जब एक गरीब और पिछड़ी जाति से आया हुआ भारत माता का लाल इस देश का प्रधान मंत्री बना और उनके द्वारा शोषित, पीड़ित और वंचितों के हित में कार्य किए जा रहे हैं, तो इन लोगों को पीड़ा हो रही है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, आज देश दोबारा अपने स्वर्णिम युग की ओर लौट रहा है। आज पूरा विश्व भारत को एक विश्वास के साथ देख रहा है कि वैश्विक समस्याओं का समाधान यदि कोई कर सकता है, तो वह सिर्फ भारत है। महोदय, अभी हाल ही में आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव भी देखे होंगे। अन्य राज्यों के भी नतीजे आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से काम किया, उसका उसे खुद मूल्यांकन करना चाहिए। सरकार द्वारा चलाई जा रही जन-कल्याणकारी नीतियों के कारण माननीय प्रधान मंत्री जी के प्रति लोगों का विश्वास दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। महोदय, उत्तर प्रदेश चुनाव में आप सभी लोगों ने एक गाना सुना होगा कि "*जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे।*" उत्तर प्रदेश में लोगों ने इसे स्वीकारा भी और लाए भी। देश की जनता ने इस बात को पूरे तरीके से स्वीकार किया है। शायद सभी लोगों ने इस गीत को सुना होगा, पर इस गीत में जो खास बात है, उसकी जो खूबसूरती है, वह यह है कि एक भगीरथ वह थे, जो माँ गंगा को पृथ्वी पर लाए और एक भगीरथ वह है, जो काशी विश्वनाथ मंदिर से कई किलोमीटर दूर बह रही गंगा माँ को काशी विश्वनाथ के नजदीक ले आए, बिल्कुल उसके पास में ले आए।

महोदय, इसी दृढ़ इच्छा-शक्ति के कारण और माँ गंगा के आशीर्वाद के कारण आज पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के ऊपर देश के प्रत्येक नागरिक का विश्वास बढ़ा है और बढ़ता रहेगा। जिस प्रकार से पिछली सरकारों ने अपनी शोषणकारी नीतियों के कारण **...(व्यवधान)...**जब आपकी सरकार थी, आप इन योजनाओं को क्यों नहीं लाए थे? आपको लाना चाहिए था। **...(व्यवधान)...**आज अगर प्रधान मंत्री जी गरीब किसानों और मज़दूरों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो आप लोगों को पीड़ा हो रही है? **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्या, आप चेयर को ऐड्रेस करें।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : पिछली सरकारों ने अपनी शोषणकारी नीतियों के कारण देश की जनता को गुमराह करने का काम किया। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : ऑनरेबल मेम्बर्स, मैं दोनों पक्षों को इंगित कर रहा हूँ। **...(व्यवधान)...**आप लोग शांति बनाए रखें और ऑनरेबल मेम्बर को बोलने दें। **...(व्यवधान)...**

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : आज जनता समझ चुकी है कि देश का कल्याण, देश का विकास, युवाओं का उत्थान, श्रमिकों का उत्थान यदि कोई कर सकता है, तो वह आज के भागीरथ, देश के करोड़ों युवाओं का विश्वास, देश की माताओं और बहनों के भाई माननीय प्रधान मंत्री, नरेन्द्र भाई मोदी जी हैं। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : ऑनरेबल मेम्बर, आप लेबर के ऊपर बोलें।

श्रीमती गीता उर्फ चंद्रप्रभा : मैं सरकार द्वारा श्रमिकों और युवाओं के उत्थान के लिए किए जा रहे कार्यों के लिए पुनः एक बार माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय श्रम एवं रोज़गार मंत्री जी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ।

अभी बहन दोला सेन जी जो बोल रही थीं, वह मैं सुन रही थी। उनकी कुछ पंक्तियाँ मेरे ध्यान में हैं। उनमें से एक पंक्ति थी- *"जुल्म की आग जलती रहेगी।"* मुझे लगता है कि यहाँ सदन में बैठे प्रत्येक माननीय सदस्य को यह लग रहा होगा कि ये पंक्तियाँ उन्हीं पर निर्भर करती हैं कि जिस तरीके से उनके राज्य में हो रहा है, जहाँ उनकी मुख्य मंत्री स्वयं एक महिला हैं। वहाँ की बेटियों और महिलाओं के साथ उनके पिता, पति और भाई को बाँधकर उनके सामने दुराचार और अत्याचार किया जा रहा है। उनको ज़रा सी दया नहीं आती। वे चीखती और चिल्लाती रह जाती हैं। **...(व्यवधान)...** वहाँ की मुख्य मंत्री में एक महिला होने के नाते ममत्व भी नहीं जागा। **...(व्यवधान)...** मैं देश के प्रधान मंत्री जी को बधाई देती हूँ कि उन्होंने देश में किसी भी विशेष जाति-धर्म के लिए काम नहीं किया। उन्होंने कभी यह नहीं माना कि इनके लिए काम करें और उनके लिए काम न करें। **...(व्यवधान)...** उन्होंने 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसी योजना लागू करके देश की बेटियों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बनाने का काम किया है, धन्यवाद।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले) : उपसभाध्यक्ष महोदयः

भूपेन्द्र यादव, आदमी बहुत ही हैं सोबर,
इसलिए मोदी जी ने उनको मंत्रालय दिया है लेबर,
मैं हूं भूपेन्द्र यादव जी का नेबर,
इसलिए मैं भी बन गया हूं सोबर,
नरेन्द्र मोदी जी का नारा है श्रमिकों को न्याय देना,
उसके बदले उनसे कुछ भी नहीं लेना,
काँग्रेस से अब मेरा कुछ भी नहीं है लेना-देना,
क्योंकि मोदी जी के पीछे खड़ी है मेरी रिपब्लिकन सेना।

आज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विषय पर चर्चा हो रही है। हमारा देश श्रमिकों की ताकत पर खड़ा है। श्रमशक्ति हमारी भक्ति है। श्रमिकों को न्याय देना हमारी ज़िम्मेदारी है। काँग्रेस ने भी उनको न्याय दिया, लेकिन थोड़ा-थोड़ा दिया। नरेन्द्र मोदी जी ने श्रमिकों के लिए 'आत्मनिर्भर भारत' योजना बनायी। श्रमिकों को न्याय देने की भूमिका रखी, सफाई मज़दूरों को न्याय देने की भूमिका रखी। चाहे गरीब समाज के मज़दूर हों, आदिवासी समाज के मज़दूर हों, ओबीसी समाज के मज़दूर हों, बहुजन समाज के मज़दूर हों या उच्चवर्णीय समाज के मज़दूर हों, सभी लोगों को न्याय देने की भूमिका हमारी सरकार की है। यह सरकार श्रमिकों के लिए काम कर रही है। भूपेन्द्र यादव जैसे विद्वान व्यक्ति को, जो बीजेपी के advocate भी हैं और उन्हें लेबर विषय पर बहुत जानकारी भी है और उनकी मज़दूरों को न्याय देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाने की कोशिश है। बेरोज़गारों को रोज़गार देने का काम हमारा है, लेकिन कॉंग्रेस पार्टी ने मुझे शिरडी में हरा कर बेरोज़गार किया था, तो मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मुझे बेरोज़गार करने वाली काँग्रेस को मैं भी बेरोज़गार करूंगा। वर्ष 2014 में काँग्रेस पार्टी बेरोज़गार हो गई। हम आपको ज़रूर रोज़गार देना चाहते हैं, लेकिन जनता आपको रोज़गार नहीं देना चाहती है। जनता के मन में एनडीए की सरकार है, जनता के मन में भारतीय जनता पार्टी है, जो 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास' की भूमिका रखती है। ऐसी सरकार को सपोर्ट करने की भूमिका मेरी पार्टी की है। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी देश के लेबर मिनिस्टर थे, वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में रहे, उन्होंने लेबर्स को न्याय देने की भूमिका रखी। उन्होंने लेबर्स के लिए 12 घंटे की ड्यूटी को घटाकर 8 घंटे करने का काम किया था, उन्होंने महिलाओं को छुट्टी देने का काम किया था, उन्होंने महिलाओं को मदद करने का काम भी किया था। इसीलिए बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जिस रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना की थी, उसी पार्टी के माध्यम से आज मैं इस सदन में खड़ा हूं। मैं लोक सभा में तीन बार सदस्य था। मैं कांग्रेस पार्टी के सपोर्ट से तीन बार सदस्य रहा, अभी मैं नरेन्द्र मोदी जी की सपोर्ट से दो बार से राज्यसभा का सदस्य हूं, मैं तीसरी बार भी आऊंगा, चौथी बार भी आऊंगा और पांचवी बार भी आऊंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, आप conclude कीजिए।

श्री रामदास अठावले : जब तक नरेन्द्र मोदी जी हैं, तब तक मैं हूं और जब मैं हूं, तब तक नरेन्द्र मोदी जी हैं। हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। लेबर मंत्रालय के संबंध में जो चर्चा हो रही है, हमारी सरकार की तरफ से लेबर्स के लिए ज़रूर अच्छा काम किया जाएगा। मेरा भूपेन्द्र जी से इतना ही निवेदन है कि जो सफाई मज़दूर हैं, उनका जो contract system है, उसको बंद करने की आवश्यकता है। जो सफाई मज़दूर होते हैं, contract labor होते हैं, उनको रिटायरमेंट तक permanent नहीं किया जाता है। इस संबंध में कोई योजना बनाने की आवश्यकता है, बंद पड़े कारखानों को भी चालू करने की आवश्यकता है और लेबर्स को न्याय देने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आप अच्छे निर्णय लेंगे। मैं दो शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : श्री रामकुमार वर्मा जी। आपके पास दस मिनट का समय है।

श्री रामकुमार वर्मा (राजस्थान) **:** उपसभाध्यक्ष महोदय, आज हम Ministry of Labour and Employment की working पर डिस्कशन कर रहे हैं। अभी एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह एक oldest Ministry है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। इसमें कोई दोराय नहीं है। यह मिनिस्ट्री इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारे वर्कर्स को empowerment करना है, उनके लिए पॉलिसीज़ बनानी हैं, योजनाओं के माध्यम से उनको strengthen करना है और विशेष रूप से organized sector के अलावा unorganized sector को भी देखना है। इस संबंध में उनका कथन बहुत अच्छा है। मैं मिनिस्ट्री से संबंधित चीज़ों पर ही बोलूंगा, मैं राजनीति नहीं करूंगा। दूसरी तरफ से बहुत राजनीति होती है। यदि इधर से कुछ बोलते हैं, तो हल्ला भी हो जाता है। इधर से राजनीति नहीं होती है, सच्चाई होती है और वे सुनते नहीं हैं। मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अभी माननीय सदस्य ने 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' वाली बात कही। उस प्रतिबद्धता के साथ राष्ट्र सर्वोपरि होगा, उसमें जनहित रहेगा। हमारे जो कार्य होंगे, उसमें भी और वे जिस पार्टी से हैं, उसका विचार भी वही है कि अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति है, उसको प्राथमिकता से उठाने का प्रयास करें। ऐसा वर्ष 2014 के बाद से हर स्कीम के माध्यम से हो रहा है। मैं उन स्कीमों में नहीं जाऊंगा, मैं केवल लेबर से रिलेटेड चीज़ों पर ही बोलूंगा। हमारे ऑनरेबल मेम्बर्स ने बताया है कि जब हमारा वर्ष 2022-23 का फाइनेंशियल बजट आया, उसमें आपने हर मंत्रालय का एलोकेशन देखा होगा। हमारा फोकस यह रहा है कि अंतिम छोर पर जो गरीब व्यक्ति है, उसका उत्थान हो। इसी तरह से मैं बजट की बात करना चाहूंगा कि Ministry of Labour and Employment के बजट की 2014 से पहले के बजट से तुलना करूं और अब तक की करूं, क्योंकि इस मंत्रालय के मंत्री माननीय यादव साहब उसके बारे में जवाब देंगे, तो मैं उन चीज़ों में उलझना नहीं चाहूंगा। यह प्रधान मंत्री की प्रतिबद्धता है कि हम किस तरह से उन मज़दूरों का और विशेष रूप से unorganized sector का भला करें, क्योंकि हमारे मंत्री महोदय जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, जिस पृष्ठभूमि से प्रधान मंत्री जी आते हैं, उन्होंने गांव और गरीब को नज़दीक से देखा है कि उनकी क्या पीड़ा होती है? वर्ष 1952 से, जब से यह मंत्रालय बना, तब से मज़दूर की बातें हुई, लेकिन कितना किया, क्या किया उसके बारे में बात न करके, मैं कहूंगा कि इस बजट की 2021-22 से तुलना करें, तो करीब यह 26.95 परसेंट increase हुआ है। एक वर्ष में ही नहीं किया, पिछले तीन वर्ष से भी आप देखेंगे, तो continuously हमारा जो BE है, उसके बाद RE है और RE के बाद बजट बढ़ा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बजट का एलोकेशन ही नहीं किया गया है, बल्कि हमारे revised budget में जो भी एलोकेशन हुआ, expenditure हुआ, वह हुआ, लेकिन इसके साथ में इतिहास यह भी बताता है कि यू.पी.ए. के समय में यह देखा गया है कि बजट तो होता था, लेकिन उसका यूज़ नहीं होता था। जो actual expenditure हुआ, उसके अंदर भी आप परसेंटेज देखेंगे, तो यह 90 परसेंट से ऊपर है, जो यह सिद्ध करता है कि हमारा commitment यह है कि जिसके लिए जो पैसा है, वह उसके उत्थान में लगना चाहिए और इस बात को यह बजट show करता है। वर्ष 2021-22 का 13,306.50 करोड़ रुपये का बजट था और अब 16,800.68 करोड़ रुपये है। मैंने जो बजट का अनुमान लगाया, वह करीब 26.95 परसेंट increase हुआ है। अगर पिछले बजट की ओर देखें, चूंकि समय नहीं है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं करूंगा। 2021-22 और 2022-23 के बजट में वृद्धि की गई है।

हमने विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से कार्य किया है। कुछ स्कीम्स आपके समय में भी थीं, लेकिन हमने उनको मोडिफाई किया है, रिवाइज़ किया है, ताकि उन स्कीम्स का केवल नाम नहीं रहे, बल्कि उनमें कार्य भी हो। इसके लिए भी allocation में वृद्धि की गई है। मैं मुख्य रूप से कहना चाहूंगा कि हमने Employees' Pension Scheme में 15 परसेंट की वृद्धि की है। हमने आत्मनिर्भर भारत के अंदर 28 परसेंट से ज्यादा की वृद्धि की है। इसके साथ-साथ establishment वाला जो expenditure है, उसको भी हमने बढ़ाया है। आप रोज़गार की बात करते है, तो मैं आगे बताऊंगा कि पहले ईपीएफ की क्या हालत थी और अब उसकी हालत बहुत अच्छी होने जा रही है। इसी तरह से मैं यह कहना चाहूंगा कि हर चीज़ के अंदर लेबर वेलफेयर की बात होनी चाहिए। National database for unorganized workers, यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है। आपकी सरकार रही है और सात दशक तक आपने काम किया है, लेकिन database के लिए आपने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की। इसके लिए हमने बजट में बढ़ोतरी की है और उसके result भी आ रहे हैं। मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। इसी तरह से मैं महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में बताना चाहूंगा। चाहे वह social security से संबंधित हो, National Career Service से संबंधित हो, coaching और guidance से संबंधित हो, एससी, एसटी, ओबीसी से संबंधित हो, unorganized sector में बीमा से संबंधित हो। इसके अंदर भी increase किया गया है। मैं यह कह सकता हूं कि यह हमारी प्रतिबद्धता है। हम slogan से काम नहीं चलाना चाहते हैं और न प्रधान मंत्री जी इसके लिए सहमत हैं। आपने मजदूरों की भलाई के लिए बहुत नारे दिए हैं। अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने trade union की बातें भी की थीं। मैं Dattopant Thengadi ji का सम्मान भी करता हूं और साथ-साथ में उधर भी, जो किसी भी पार्टी से related थे, Ashis Sen ji रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी थे, वे उसमें आए थे। उसके बाद वसीयत भी उनके पास है, मैं समीर घोष जैसे लोगों का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मुझे ट्रेड यूनियन का 40 साल का अनुभव है कि ट्रेड यूनियन का कार्य किस तरह से हुआ। जैसा पूर्व वक्ताओं ने हमें बताया, मैं उन्हीं की बात पर कुछ कहकर अपनी बात खत्म करता हूं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा और ये सुनेंगे भी नहीं। ट्रेड यूनियन employment के प्रोटेक्शन के लिए एक movement होता है, लेकिन कुछ समय बाद ट्रेड यूनियन के movement का affiliation किसी पार्टी विशेष के साथ हो गया था और monopoly करके वहां जितने वर्कर्स थे, उनका exploitation शुरू हो गया था और उनका पतन भी हुआ। सर, मैं ईपीफ की बात करना चाहूंगा कि मजदूरों की social security के लिए हमने कितना कार्य किया। उनका जो पैसा है, हमारे पास corpus है, हम जो invest कर रहे हैं, उसे हम कहीं commercial bond की तरह नहीं कर रहे हैं। उस पर हम बहुत सुरक्षित ढंग से कार्य कर रहे हैं, जिससे कि उसका जो रिटर्न है, वह 6.6 परसेंट से लेकर 8 परसेंट तक मिल रहा है। इससे निश्चित ही हमारे जो कर्मचारी या स्टाफ हैं, उनको ईपीएफ में फायदा मिलेगा। हमारे इन्हीं प्रयासों के कारण आज मंत्री जी ने EPFO के लिए करीब दो हज़ार भर्तियों की शुरूआत कर दी है और उनके पास manpower बढ़ेगी। इस तरह के decision हमारी सरकार ने लिए हैं। उनके प्रमोशन्स और उनके लिए सुधार की बहुत सारी बातें भी हुई हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जिसे आपने कभी नहीं सोचा था कि unorganized sector को हम किस तरह से regularized करें। आप भी आंकड़े दिया करते हैं और बहुत जोर से बोलकर कहते हैं कि 50 करोड़ unorganized sector के लोग हैं और कोई कहता है कि 40 करोड़ हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, कन्क्लूड करें।

श्री रामकुमार वर्मा : मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि e-SHRAM पोर्टल के माध्यम से हमने अगस्त, 2021 में जो शुरुआत की - आपको ताज्जुब होगा कि इसमें छह महीने के अंदर 26 करोड़ से अधिक लोग रजिस्टर हुए हैं, यह कोई छोटी बात नहीं है। यह उसी तरह से है कि आपने 2014 तक बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर सिर्फ 12 करोड़ लोगों के अकाउंट्स खोले थे। लेकिन छह महीने के अंदर, बारह महीने के अंदर 48 करोड़ अकाउंट्स खुले - यह इस तरह से हुआ। जो e-portal से आए, उसमें छोटे-छोटे मजदूर, ठेली लगाने वाले, खोमचा लगाने वाले, रेस्टोरेंट में काम करने वाले, प्रवासी, gig workers, दूध वाले, आशा कार्यकर्ता आदि सभी लोग एग्रिकल्चर से संबंधित हैं। अभी हमारे एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि आपने एग्रिकल्चर के लिए क्या किया? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इसके अंदर एग्रिकल्चर के वर्कर्स, भूमिहीन वर्कर्स भी हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो e-portal है, उसमें पूरा डेटा होगा, उसमें फैमिली का डेटा होगा कि वे क्या करते हैं। इसके बाद ही, उनको लेकर हमारी जो योजना बनेगी, उससे उनको फायदा होगा। **..(व्यवधान)..**

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : कृपया, आप conclude कीजिए।

श्री रामकुमार वर्मा : महोदय, मैं बस एक मिनट में खत्म करता हूं। मैंने जो बहुत सारी योजनाओं की बात कही है, उनके लिए बस यही कहूंगा कि आज प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसको मंत्रालय भी पूरा कर रहे हैं और देश की जनता उसी तरह से सोचकर उसके परिणाम भी दे रही है। मैं समझता हूं कि जिस तरह की प्रधान मंत्री जी की प्रतिबद्धता है, आने वाले समय में यह देश उस तरह से समृद्ध होगा और मजदूर, जिसे न्याय नहीं मिला, उसे वह न्याय, जो आप नहीं दे पाए इन श्रम कानूनों से भी मिलेगा, पॉलिसीज़ से भी मिलेगा और स्कीम्स से भी मिलेगा। उपसभाध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आपका धन्यवाद। माननीय सैयद नासिर हुसैन जी, आप अपना भाषण आरंभ कीजिए।

SHRI SYED NASIR HUSSAIN (Karnataka): Thank you, Sir, for giving me an opportunity to speak on the working of the Ministry of Labour and Employment.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Because of the time overrun by your previous speaker, you have got one minute. You can take a few more minutes.

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, एक मिनट तो बैठकर उठने में ही हो जाएगा।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): I am just saying that you take a few more minutes and make your statement.

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, काफी लोगों ने ऑलरेडी बात कह दी है। अभी हमारी एम.पी. श्रीमती वंदना चव्हाण जी, जब लास्ट में बात कह रही थीं, तो उन्होंने बोला कि we have already forgotten that we are a welfare state. We are a democratic state. Any democratic state will essentially have to be a welfare state. The Ministry of Labour and Employment covers almost 50-60 crore Indians. It is its duty not only to safeguard and protect the labour force of our country but also to see that there are enough jobs for the people in our country. Like all Governments, this Government has its orientation. It has its own ideological positioning. It has its own policy intervention which makes it very, very clear that this Government, as we all have been speaking, is pro-capitalist. This Government is pro-big business. This government is pro-cronyism. This is a '*suit-boot ki sarkar*'. That is the reason why we call it a '*suit-boot ki sarkar*'. सर, सिर्फ यही नहीं, बल्कि सारे मंत्रालयों में इनकी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, उनको देखने से यह एकदम साफ होता है कि यह सरकार लगातार privatization, लगातार PSUs को बेचने, लगातार disinvestment में लगी है, जिसका हमारी लेबर के ऊपर जबरदस्त असर पड़ा है। इसकी वजह से they are under tremendous stress in our country. Everyone knows it. Everything is getting privatized. There are no jobs. Nothing. अभी one of my friends, बीजेपी से एक सीनियर लीडर, शुक्ल जी बात कर रहे थे, वे PSUs के बारे में कह रहे थे कि हम लोगों ने 'मेक इन इंडिया' का स्लोगन नहीं दिया था, मोदी जी के आने के बाद 'मेक इन इंडिया' का स्लोगन दिया गया। हिंदुस्तान में जो 370 से ज्यादा PSUs हैं, उनमें majority 80-90 per cent PSUs कांग्रेस की regime में, कांग्रेस के रूल के टाइम पर बनी थीं। ये जो HAL, BHEL, BEML हैं, इनको बनाकर ये 'मेक इन इंडिया' नहीं कर रहे थे, तो क्या कर रहे थे? हम लोग खोखले स्लोगन्स नहीं देते हैं, बल्कि हम लोग काम करते हैं। हम लोगों ने जो PSUs बनाए थे, उनको बेचने का काम यह सरकार लगातार कर रही है। जब हिंदुस्तान में एक ऐसी सिचुएशन है और लेबर पर लगातार मार पर मार पड़ रही है, तब हमारी सरकार लेबर कोड्स लेकर आती है। हमारी सरकार लेबर कोड्स लाकर एम्प्लॉयर को sweeping powers देती है। Hiring and firing बहुत आसान हो जाता है, unionism कर नहीं सकते हैं, strike कर नहीं सकते, bargain कर नहीं सकते, negotiate कर नहीं सकते। यहाँ हिंदुस्तान में digitalization हो रहा है, digitalization का नारा लगातार दिया जाता है। Digitalization होता है, तो उससे computerisation होता है। चाहे ऑफिसेज़ में हो, चाहे फैक्ट्रीज़ में हो, चाहे मिल्स में हो, लोगों के काम करने की तादाद कम होती जा रही है, क्योंकि हम लोग digitalization पर ज्यादातर depend हो रहे हैं। जब तादाद कम हो रही है, तो आप यूनियन बनाने की संख्या क्यों बढ़ाते हैं? आप 100 से 300 कर देते हैं - इसका मतलब है कि जहाँ कम संख्या में लोग हैं, वहाँ पर यूनियन नहीं हो सकती है। They don't have any right to negotiate. They don't have any right to bargain with their employers. ये sweeping powers, जो employers को दे रहे हैं, again

this shows that this sarkar is completely pro-big business and this sarkar is completely pro-capitalist. यहां पर बात हो रही थी कि हम लोगों ने 2014 के बाद में, यह सरकार आने के बाद में ऐसा काम किया, वैसा काम किया। यह सरकार hollow slogans की सरकार है, यह सरकार बड़े खोखले स्लोगंस देती है, लेकिन कभी-कभी बजटरी एलोकेशंस भी कर देती है। हम लोगों की 2014 के पहले जो स्कीम्स होती थीं, हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे, हमारे जो लेबर मिनिस्टर्स रहते थे, हमारे LoP भी लेबर मिनिस्टर थे, हमारे पहले लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम जी थे, लेकिन हमारे लेबर मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खरगे साहब ने, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिये, हम लोगों ने बहुत सारी स्कीम्स दीं, लेकिन जब budgetary allocations होता था तो हम लोग पूरी कोशिश करते थे कि जो एलोकेशन हुआ है, उसका पूरा इस्तेमाल हो और हम उस पूरी स्कीम को इम्प्लीमेंट करें, उसे ज़मीन तक लेकर जायें, मज़दूर तक उसे पहुंचायें और हम लोग उसे गरीब तक पहुंचाने का काम करते थे।

अब मैं यहां पर कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। मेरे से पहले जो माननीय सदस्य बात कर रहे थे, वे लगातार कुछ आंकड़े दे रहे थे। Labour Codes का तो इन्होंने violation किया ही है, International Labour Convention का, C144-Tripartite Consultation का इन्होंने वायलेशन किया ही है और हमें लेबर मिनिस्टर साहब बीच में इंटरवीन करके बता रहे थे कि consultations काफी हुए हैं। अगर consultations हुए होते तो हमारे top ten Central Labour Unions ILO क्यों जाते? उनको क्यों चिट्ठी लिखते और वहां से ILO के Director General यहां पर प्राइम मिनिस्टर नरेन्द्र मोदी जी को चिट्ठी क्यों लिखते, इंक्वायर क्यों करते कि देखिये, इसका वायलेशन क्यों हो रहा है?

इस दौरान भी हिन्दुस्तान के कोने-कोने में बहुत सारे agitations हो रहे हैं, कहीं contract workers कर रहे हैं तो कहीं मिल्स में agitations हो रहे हैं। यहां तो Ordnance Factory में भी agitation हुआ था, उन लोगों से बातचीत करने के बजाय, मसला हल करने के बजाय, उसके बाद ये एक Ordinance लेकर आ गये। इसके कारण बेंगलुरू में 6 महीने से Indian Telephone Industry Limited, 1941, It was one of the first PSUs, वहां पर 100 से ज्यादा वर्कर्स पिछले 6 महीने से agitation कर रहे हैं। इनके चीफ लेबर ऑफिसर ने intervene किया, स्टेट के चीफ लेबर ऑफिसर ने intervene किया, टेलीकम्युनिकेशन के सैक्रेटरी ने intervene किया और COPU का मैं मैम्बर हूं, कोपू के चेयरमेन श्री संतोष गंगवार साहब ने भी intervene किया, लेकिन उस मसले का हल नहीं हुआ। वे वहां पर बाहर सड़कों पर बैठे हुए हैं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य conclude करें। Please try to conclude.

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, अभी तो मैंने शुरू किया है।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): You have already overrun by five minutes. I have given you five more minutes. Just conclude in another two minutes.

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं, लेकिन मैं सीधे बजट पर आता हूं। बजट में एलोकेशन पिछली बार से थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन मिनिस्ट्री के जो थोड़े Grants थे, उन Grants में जो पूछा गया, उससे कम था। आप इसे देखिये कि कम क्यों हुआ, क्योंकि हर स्कीम में जितना एलोकेशन पिछली बार हुआ था, उससे कम इस्तेमाल किया गया है। मैं मात्र दो स्कीम्स का बताऊंगा, एक स्कीम एम्पलाइज़ पेंशन वाली है और दूसरी पी.एम. रोज़गार प्रोत्साहन योजना वाली है, सिर्फ इनमें 100 परसेंट इस्तेमाल हुआ था, बाकी की सारी स्कीम्स आप देखिये, उनमें 12.63 से लेकर 29.84 परसेंट के बीच में इसका इस्तेमाल हुआ है। मैं अब लिस्ट नहीं दूंगा, क्योंकि मैं यहां पर पेपर्स रखूंगा, उससे एकदम क्लियर हो जायेगा।

एक चीज़ के बारे में मैं जरूर बात करना चाहूंगा, NCLP (National Child Labour Project) के बारे में, क्योंकि मैंने उसके वाइस चेयरमैन के रूप में तीन साल तक काम किया है तो अभी NCLP को इन लोगों ने मार्च के महीने में समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया है। NCLP को समझना चाहिए था, राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पर 1988 में उसे स्टार्ट किया गया था, जो नौ साल से 14-15 साल के बीच में हमारी child labour है, उसे rescue करके लेकर आते हैं, उसे लाकर उसे bridge education देना, उसे skill education देना, उसे health facility देना, उसे stipend देना, यह काम तो किया, लेकिन आप सीधे उठाकर उसे अगर regular schools में डाल देंगे तो child labour वहां पर मेरे ख्याल से cope up नहीं कर पाएगा। उसके साथ में वहां पर जो करीब 2,000 स्टाफ था, उनकी जो district level पर society थी और child labour के लिए 6,000 special schools थे, उन 6,000 स्कूल्स में जो 30,000 टीचर्स काम करते थे, जो स्टाफ काम करता था, प्लस सोसाइटीज़ में जो 2,000 लोग काम करते थे, 32-35 हजार लोग जो वहां पर काम कर रहे थे, उनका क्या होगा? अगर हम उन लोगों को दरकिनार कर देंगे तो वे लोग कहां जाएंगे? पहले stipend 400 रुपये का चाइल्ड लेबर को दिया जाता था, to attract the child labour **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : अब आप conclude करें। Take a minute and conclude.

श्री सैयद नासिर हुसैन : सर, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जिन्हें मैं बोलना चाहता था, लेकिन चूंकि टाइम नहीं है, इसलिए मैं लेबर मिनिस्टर से सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा कि Periodic Labour Force Survey पहले हुआ करता था, अब यह कुछ सालों से नहीं हो रहा है, क्योंकि जैसे ही आंकड़े नकारात्मक आने लगे तो इन्होंने उसका सर्वे ही बन्द करवा दिया।

7.00 P.M.

आप इसका सर्वे करवाने और निकलवाने के लिए क्या step लेंगे, उसके बारे में बताइएगा। सर, इसके साथ ही बहुत सारे issues हैं, मैं उनके ऊपर आँकड़े देना चाह रहा हूँ। हर स्कीम में कम पैसा खर्च किया गया है। यह एकदम साफ दर्शाता है कि ये प्रो-लेबर नहीं हैं, प्रो-मजदूर

नहीं हैं और प्रो-किसान नहीं हैं। सिर्फ एक नारा, जो हम लोग हमेशा लगाते हैं, उसे बोल कर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ:

"श्रम की कीमत, श्रम का मान,
माँग रहा है मजदूर-किसान।"

आप लोग divisive tactics अपनाकर, polarize करके चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मजदूर-किसानों में से किसान तो 14 महीने धरने पर बैठे, आप Labour Code वापस लीजिए, scrap कर दीजिए, कहीं ऐसा न हो कि फिर मजदूरों को भी हिन्दुस्तान भर में 14-15 महीने आपके खिलाफ बैठना पड़े! जय हिन्द!

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): माननीय श्री संजय सिंह जी। आपके पास कुल 4 मिनट हैं।

श्री संजय सिंह (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली): मान्यवर, जैसे आपने सबका समय बढ़ाया है, थोड़ा समय मेरा भी बढ़ा दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा): नहीं, सभी की स्पीच समय से खत्म हो रही है।

श्री संजय सिंह: मान्यवर, आपका धन्यवाद कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। हमारे यहाँ अवधी के एक कवि हुए- जमुना प्रसाद उपाध्याय जी, उनकी एक लाइन थी कि :

"धान से, गेहूँ से जब गोदाम सारे भर गए,
पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया?
इन फिज़ाओं में ज़रा सी जो रोशनी है, हमसे है,
देश को इन लाल-नीली बत्तियों ने क्या दिया?"

मान्यवर, इस देश का श्रमिक, इस देश का लेबर, जो मेहनत से, मजदूरी से बड़ी-बड़ी इमारतें खड़ी करता है, हमारे-आपके घर भी खड़े करता है, खेत में भी मजदूरी करके पसीना बहाता है। वह बड़े-बड़े employers के यहाँ, बड़े-बड़े उद्योगपतियों के यहाँ नौकरी करता है। वह अपने श्रम से इस देश को बनाने का, सँवारने का, सजाने का काम करता है। अगर हम उसकी दशा देखना चाहें, तो हम कोरोना की इस महामारी को याद कर लें, तो पता चल जाएगा कि देश के श्रमिकों के साथ इस देश की सरकार का क्या व्यवहार था! मान्यवर, वे भूखे मजदूर पैदल ट्रेन की पटरियों पर चलते चले जा रहे थे। वे थक गए, तो अपने घर से जो खाना बना कर निकले थे, उसको पटरी पर बैठ कर खाने लगे। वे और थक गए, तो खाने के बाद उन्हें उसी पटरी पर नींद आ गई, उन्हें पता नहीं चला और ट्रेन ने उनको कुचल कर मार दिया। मान्यवर, यह इस देश के मजदूरों की हालत है! मैं उस दिन यहाँ पर कुलियों के बारे में बोल रहा था। एक फिल्म बनी थी - कुली। "सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं।" मान्यवर, उन कुलियों के लिए रेल मंत्रालय ने एक समय में उनके परिवार के लोगों को नौकरी देने का निर्णय लिया था, जब लालू प्रसाद यादव जी रेल मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज तक उसके compliance की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने खुद 16 साल तक असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के साथ काम किया। मैंने रिक्शे वालों के

बीच काम किया, ऑटो वालों के बीच काम किया, 16 साल तक hawkers के बीच काम किया। वे दिन भर बड़ी मेहनत से अपनी दुकान को सजाते हैं, बड़ी मेहनत से धूप में, गर्मी में, बारिश में फल बेच कर, सब्जियाँ बेच कर पैसे कमाते हैं और डंडे मार कर पुलिस वाला उनसे उनकी कमाई में हिस्सा बाँटने आ जाता है। यह इस देश के मजदूरों की हालत है! सर, मैं तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तारीफ करूँगा कि उन्होंने 2004 में इस देश के अन्दर National Policy on Urban Street Vendors लागू की थी और बाद में कांग्रेस की सरकार ने एक एक्ट लागू किया। उसने इस देश में एक एक्ट बनाया। इस देश के असंगठित क्षेत्र में और खास तौर से पटरी-गुमटी पर काम करने वाले, रेहड़ी-पटरी पर काम करने वाले करोड़ों लोगों के हक में, करोड़ों मजदूरों के हक में एक फैसला लिया गया और vendors के लिए एक्ट बनाया गया। उन श्रमिकों के लिए, उन vendors के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है, जब आप जवाब दें, तो बताइएगा। हालाँकि आप कह सकते हैं कि यह urban development से जुड़ा हुआ मामला है, जिस कमिटी का मैं मेम्बर हूँ, लेकिन आज उनकी दशा यह है कि सरकार की ओर से, प्रधान मंत्री जी की ओर से 10-10 हजार रुपए की सहायता देने की बात कही गई थी, वे अपना 10 हजार पाने के लिए बैंकों के 10-10 चक्कर लगाते हैं। 250 रुपए का शपथ पत्र दो, 100 रुपए का शपथ पत्र दो, 500 रुपए का शपथ पत्र दो, यह formality पूरी करो, वह formality पूरी करो, यह आपका नज़रिया है गरीब आदमी के प्रति! आप अगर इस पूरे कानून को पढ़ेंगे, इसमें होने वाले बदलावों को पढ़ेंगे, तो समझ सकते हैं कि सीधे-सीधे यह employers के पक्ष में है, employees के पक्ष में नहीं है। यह कानून श्रमिकों के पक्ष में नहीं है, उद्योगपतियों के पक्ष में है, बड़े-बड़े घरानों के पक्ष में है। यह कानून श्रमिकों के शोषण की एक नई कहानी लिखेगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : आप अब खत्म कीजिए।

श्री संजय सिंह : मैं बस अपनी बात खत्म ही कर रहा हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं, आपके ऊपर एक बहुत अच्छी और बड़ी जिम्मेदारी है। मैं आदरणीय भूपेन्द्र यादव जी को एक अच्छे मंत्री के तौर पर, एक संवेदनशील व्यक्ति के तौर पर मानता हूं। मेरा अनुरोध है कि आप मज़दूरों के प्रति अपनी संवेदना दिखाइए और उनके हित में काम कीजिए, जिससे उनके शोषण की जो कहानी है, उसको रोका जा सके।

महोदय, मैं 'Street Vendors Act' के बारे में बात कर रहा था। इस देश में चाहे vendor zone बनाने की बात हो, TVC गठित करने की बात हो, फुटपाथ के लोगों को अधिकार देने की बात हो या रोज़गार देने की बात हो, यह कहीं नहीं हो रहा है। जहां मन में आता है, बुलडोज़र चला कर उखाड़ दिया जाता है। ये सब तो वैसे भी बुलडोज़र वाले लोग हैं, जहां मन हुआ गरीब आदमी पर बुलडोज़र चला दिया और उजाड़ कर फेंक दिया। अभी नोएडा का एक दृश्य आप सब लोगों ने देखा होगा, एक गन्ने की दुकान वाला आदमी रो रहा था।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जब आप एक बड़े तबके के लिए, करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाने जा रहे हैं या उसमें कोई संशोधन करने जा रहे हैं, तो कम से कम उनके हितों को सर्वोपरि रखिए। चाहे वह रिक्शे वाला हो, ऑटो वाला हो, वेंडर हो, रेहड़ी-पटरी पर दुकान

लगाने वाला हो, उनके हितों की रक्षा करने का काम आप कीजिए और उनके हितों को सुरक्षित करने का काम आप कीजिए। आपने मुझे इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री जयप्रकाश निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने मुझे श्रम और रोज़गार जैसे विषय पर बोलने का अवसर दिया। हम अपने देश के यशस्वी प्रधान मंत्री, आदरणीय मोदी जी के भी आभारी हैं। श्रम और रोज़गार मंत्री जी की कार्यकुशलता के लिए भी मैं उनका धन्यवाद करता हूं।

महोदय, श्रम एवं रोज़गार दो ऐसे मानक हैं, जिनसे एक देश की, एक राष्ट्र की स्थिति का भली-भांति आकलन किया जा सकता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हम सबने बीते कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में कई विकासशील बदलाव देखे हैं, जिनका प्रभाव देश के अन्य विकास कार्यों में भी प्रतिबिम्बित हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, आज अपने देश में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व में उनकी चर्चा हो रही है, यह हम सबने देखा है। अभी हमारे एक वरिष्ठ सदस्य अपनी बात कह रहे थे, वे कह रहे थे कि इस सरकार को बेरोज़गारी की चिंता नहीं है। हमको तो लगता है कि बहुत सारे लोगों को, जो राजनीति से बाहर जाते जा रहे हैं, उन्हें अपनी राजनीतिक बेरोज़गारी की चिंता अधिक हो रही है।

महोदय, वर्ष 2021-22 में श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय को 13,306.5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, जिसे इस वर्ष बढ़ा कर 14,248.72 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह हमारे मंत्री जी की उपलब्धि नहीं है, तो और क्या है? यह माननीय प्रधान मंत्री जी की उपलब्धि नहीं है, तो और क्या है? क्या यह इन लोगों को नज़र नहीं आता है?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी महसूस हो रही है कि अधिकांश अन्य योजनाओं के लिए व्यय का प्रतिशत 60 से 92.6 तक रहा है। 'कर्मचारी पेंशन योजना' और 'प्रधान मंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना' के संदर्भ में व्यय का प्रतिशत 100 में से 100 रहा है। यह बेरोज़गारी को दूर करने के लिए बहुत बड़ी बात है।

महोदय, कोरोना महामारी जैसी विषम विभीषिका के बावजूद भी वर्ष 2021-22 के दौरान 1,097 रोज़गार मेलों का आयोजन किया गया, जिनमें 18 उद्योगों के 2,285 नियोक्ताओं ने भाग लिया था। यह माननीय प्रधान मंत्री जी और हमारे माननीय मंत्री जी के सहयोग से संभव हुआ। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इस रोज़गार मेले के माध्यम से नामांकित लाभार्थियों को कौशल प्रदान करने के साथ-साथ सेवा, वितरण और आईटी बुनियादी ढांचे में सुधार की दृष्टि से मंत्रालय ने इसमें टाइम्स जॉब, टीसीएस आदि प्रमुख संगठनों को शामिल किया है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि असंगठित कामगारों के कल्याण हेतु एक राष्ट्रीय डेटा बेस बनाते हुए ई-श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, योजनाओं के वितरण की सुविधा प्रदान कराना है। इस डेटा बेस में निर्माण श्रमिक, प्रवासी श्रमिक, गिग वर्कर, प्लेटफॉर्म वर्कर, कृषि श्रमिक, मनरेगा कार्यकर्ता, मछुआरे, दूधवाले, आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, रेहड़ी-पटरी वाले, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक असंगठित क्षेत्र के इसी तरह के अन्य व्यवसायों में लगे अन्य श्रमिक भी शामिल होंगे। इनके माध्यम से केन्द्र तथा राज्य

मंत्रालय के द्वारा श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। इसके माध्यम से सभी असंगठित श्रमिकों एवं निर्माण श्रमिकों को 'प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना' के तहत एक वर्ष के लिए दो लाख रुपये के दुर्घटना बीमा कवर का निःशुल्क लाभ प्रदान किया जा रहा है।

महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी श्रमिकों की बहुत चिंता करते हैं। जनवरी, 2022 तक 22. 85 करोड़ से अधिक श्रमिकों को ई-पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। 34.9 प्रतिशत पंजीकृत श्रमिकों के साथ उत्तर प्रदेश में सबसे अग्रणी योगी सरकार ने अपनी भूमिका निभाने का काम किया है।

महोदय, इसी के साथ मैं आपका ध्यान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आम तौर पर ईपीएफओ का आंकड़ा औपचारिक क्षेत्र के मध्यम एवं बड़े प्रतिष्ठानों में कम वेतन पाने वाले श्रमिकों को शामिल करता है, परन्तु इसमें हुई वृद्धि मौजूदा रोज़गार को औपचारिक रूप देने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

महोदय, 2021 के दौरान ईपीएफओ सब्सक्रिप्शन में मासिक वृद्धि दर्ज की गई है, यह मासिक वृद्धि शुद्ध रूप से न केवल 2020 में संबंधित मासिक मूल्यों से अधिक रही है, बल्कि उसने पूर्व महामारी वर्ष 2019 के स्तर को भी पार कर लिया है। यह दर्शाता है कि न केवल जॉब मार्केट औपचारिकता की ओर अग्रसर हो रहा है, अपितु नई हायरिंग में भी बढ़ोतरी हो रही है। 18 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के कर्मचारी, जिनकी मासिक आय 15 हज़ार रुपये या उससे कम है, जिसकी वजह से वे ईपीएफओ अथवा कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य नहीं बन सके, उनके लिए केन्द्र सरकार ने वर्ष 2019 में 'प्रधान मंत्री श्रमयोगी मानधन योजना' की शुरुआत की थी। इसके माध्यम से अब तक 46.09 लाख लाभुकों का नामांकन किया जा चुका है, जिनमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। यह मोदी सरकार द्वारा बदलते भारत की नई तस्वीर को दर्शाता है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री जयप्रकाश निषाद : मान्यवर, मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, मैं जानता हूं कि समय का अभाव है। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊँगा। मैं कम शब्दों में अपनी बात कहूँगा। हमारे माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सपना देखा था कि अन्तिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुँचे तथा उसे रोटी, कपड़ा और मकान एवं रोजगार उपलब्ध हो। माननीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह जो सपना देखा था, उस सपने को हमारे देश के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय मोदी जी पूरा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, गरीबी क्या होती है, उन मजदूरों के साथ कौन है, जब तक माननीय मोदी जी की सरकार नहीं आयी थी, तब तक उन मजदूरों की हालत क्या थी। आज मैं वनटांगिया के मजदूरों का हाल बताता हूँ। वे दर-दर भटकते थे। उनको कोई पूछने वाला नहीं होता था। ये सरकारें न ही उनको राशन देती थीं, न ही उनको मिट्टी का तेल देती थी। उनको अंधेरे में रहने के लिए मजबूर कर दिया गया था। लेकिन, इस देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने वनटांगिया को राजस्वग्राम घोषित करके उन लोगों को सारी सुविधाएँ, निःशुल्क राशन, निःशुल्क सिलेंडर, निःशुल्क सारी सुविधाएँ देकर उनके घर में, उनके जीवन में उजाला पैदा करने का काम किया है।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोविड महामारी का दौर आया, तब हम लोगों ने देखा कि उनके पास मास्क उपलब्ध नहीं था, उनके पास बहुत सारे बचाव के उपाय नहीं थे। इस देश के प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लिए, सब लोगों को जागरूक करके सबके लिए काम करने का काम किया।

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : माननीय सदस्य, अब आप कन्क्लूड करें।

श्री जयप्रकाश निषाद : मान्यवर, मैं समय के अभाव को समझ रहा हूँ। मैं अपनी बात को विराम देने से पहले अपने पूर्व प्रधान मंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता क्वोट करूँगा: *" भूखों को गोली, नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं।"* यानी जो लोग आज बहुत बड़े-बड़े सुझाव दे रहे हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ:

"भूखों को गोली नंगों को हथियार पिन्हाए जाते हैं।
सूखे कंठों से जेहादी नारे लगवाये जाते हैं।।
लाहौर, कराची, ढाका पर मातम की है काली छाया।
पख्तूनों पर, गिलगिट पर है ग़मगीन ग़ुलामी का साया।।
बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है।"

इसीलिए इस देश को मोदी जी बहुत जरूरी हैं।

"कैसे उल्लास मनाऊँ मैं, थोड़े दिन की मजबूरी है।।
दिन दूर नहीं खंडित भारत को पुनः अखंड बनायेंगे।
उस स्वर्ण दिवस के लिए आज से कमर कसें बलिदान करें।
जो पाया उसमें खो न जायें, जो खोया उसका ध्यान करें।
बस इसीलिए तो कहता हूँ आज़ादी अभी अधूरी है।"

उपसभाध्यक्ष (डा. सस्मित पात्रा) : धन्यवाद।

श्री जयप्रकाश निषाद : इस भारत की जनता के लिए, श्रमिकों के लिए, भारत के लिए मोदी जी बहुत जरूरी हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SASMIT PATRA): Now, Special Mentions. Shri Rajendra Gehlot; not present. Shri Tiruchi Siva; not present. Now, Ms. Dola Sen. This is just to let everyone know that the reply will be made in the next Business time.